● वर्ष-6
● अंक-66
रायपुर, गुरुवार
15 अक्टूबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-8›› जशपुरनगर में 11.83 करोड़ ...

मोदी कैबिनेट : सामाजिक सुरक्षा योजना पर 53,428 करोड़ रुपये खर्च होंगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों, सामाजिक सुरक्षा और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने करीब 11.40 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का उत्पादकता आधारित बोनस देने, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने और आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी देने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन फैसलों में रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान खास तौर पर महत्वपूर्ण है, वहीं पेंशन योजनाओं में बदलाव से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाने की तैयारी है। इसके अलावा, कैबिनेट ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 53,428 करोड़ रुपये के कुल बजट को मंजूरी दी है। इस फैसले से देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में करीब 3.20 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसके तहत योजना और उसकी उप-योजनाओं के नाम बदले जाएंगे। पहले इन योजनाओं के नाम इंदिरा गांधी के नाम पर थे।

साथ ही कैबिनेट ने दिव्यांगजन पेंशन के लिए पात्रता में बड़ा बदलाव करते हुए निर्धारित दिव्यांगता का मानदंड 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया गया है। न्यूनतम आयु की शर्त भी जन्म से लागू करने का



फैसला लिया गया है। दिव्यांगजन पेंशन की सहायता राशि 0 से 79 वर्ष की आयु के लिए 375 रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए 625 रुपये निर्धारित की गई है। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन तथा परिवार लाभ योजना मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी।

11.40 लाख रेलवे कर्मचारियों को 2,009 करोड़ रुपये का बोनस

कैबिनेट ने रेलवे के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस (पीएलबी) देने की मंजूरी दी है। इस पर कुल 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये मिलेंगे। ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और अन्य ग्रुप-सी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। मोदी सरकार ने यह फैसला ऐसे समय लिया है, जब रेलवे ने माल ढुलाई का नया रिकॉर्ड कायम किया साथ ही करीब 7.41 अरब यात्रियों को सफर कराया। बोनस को रेलवे कर्मचारियों के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने और उनकी मेहनत को मान्यता देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

आईडीबीआई बैंक की बिक्री पर बड़ा फैसला

वहीं बैंकिंग क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाया है। आईडीबीआई बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारीफेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की सहायक कंपनी को 52,878.08 करोड़ रुपये में बेचने की मंजूरी दी गई है। इस सौदे में केंद्र सरकार की 30.48 प्रतिशत और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल है। सौदा पूरा होने के बाद सरकार के पास 15 प्रतिशत और एलआईसी के पास 19 प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी। दोनों की संयुक्त हिस्सेदारी 34 प्रतिशत होगी। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, सौदा पूरा होने पर यह भारत के वित्तीय क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) होगा। बहरहाल, कैबिनेट के फैसलों में रेलवे कर्मचारियों को आर्थिक राहत, बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा निवेश और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार तीन प्रमुख संदेश हैं। अब इन फैसलों का वास्तविक असर उनके समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

मतगणना का वीडियो ही गायब हो गया..., कोर्ट ने चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत के चुनाव आयोग के इस दावे पर कड़ी आपत्ति जताई कि वह कर्नाटक के श्रृंगेरी विधानसभा क्षेत्र में 2023 में हुई वोटों की गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं ढूंढ पाया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर आयोग उपलब्ध रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहता है, तो उसके खिलाफ़ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाएगा। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने ईसीआई से कहा कि भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) यह कैसे कह सकता है कि उसने अपना रिकॉर्ड खो दिया है? आपका मुख्य काम चुनाव कराना है और आपके पास डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। यह कहने का क्या मतलब है कि हां, हम उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं? आपने उसे चुने हुए उम्मीदवार को दे दिया था। रिकॉर्ड की कोई कस्टडी ही नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है, उसे अगली तारीख पर पेश करें। वरना, हमें आपके खिलाफ़ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। हम इस तरह के कमजोर बहाने स्वीकार नहीं करेंगे। कोर्ट कांग्रेस नेता टीडी राजेगौड़ा की याचिका पर सुनवाई कर



रहा था। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार डीएन जीवराज को 201 वोटों के मामूली अंतर से हराया था, लेकिन बाद में उस निर्वाचन क्षेत्र में पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था।

जब राजेगौड़ा ने चुनाव ऑब्ज़र्वर की रिपोर्ट और 2023 में हुई ओरिजिनल गिनती और इस साल मई में हुई दोबारा गिनती के वीडियो रिकॉर्डिंग देखने की मांग की, तो ईसीआई ओरिजिनल गिनती की फुटेज का पता लगाने में नाकाम रही, जिस पर बेंच ने उसे फटकार लगाई। जब कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश देने का प्रस्ताव रखा, तो श्वष्टद्बद्द की ओर से पेश सीनियर वकील शेषद्रि नायडू ने कहा कि ओरिजिनल गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकी। इस दलील से बेंच संतुष्ट नहीं हुई और उसने आयोग से कहा कि अगली सुनवाई तक जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध हों, उन्हें पेश किया जाए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी, 2027 तय की।

गायब फुटेज इसलिए अहम है क्योंकि विवाद पोस्टल बैलेट के साथ किए गए व्यवहार और उस प्रक्रिया की वैधता पर केंद्रित है, जिसके कारण राजेगौड़ा की चुनावी जीत पलट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मई में ईसीआई को निर्देश दिया था कि वह कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर हुई दोबारा गिनती से जुड़े संबंधित रिकॉर्ड पेश करे और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उठाए गए सभी संबंधित कदमों को आगे की जांच तक रोक दे। यह विवाद कर्नाटक हाई कोर्ट में जीवराज द्वारा दायर एक चुनावी याचिका से शुरू हुआ, जिसमें राजेगौड़ा की जीत को चुनौती दी गई थी। 6 अप्रैल, 2026 को हाई कोर्ट ने पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती का आदेश दिया, जिसमें उन 279 बैलेट की दोबारा जांच भी शामिल थी जिन्हें शुरुआती गिनती के दौरान खारिज कर दिया गया था।



कार्टून समाज को सोचने-आत्ममंथन के लिए करता है प्रेरित : मुख्यमंत्री

रायपुर। कार्टून केवल हास्य और मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतंत्र और समाज का सशक्त दर्पण है। यह गंभीर विषयों, सामाजिक परिस्थितियों और विसंगतियों को हास्य एवं व्यंग्य के माध्यम से सहजता से जनमानस तक पहुंचाने वाली प्रभावशाली रचनात्मक विधा है। कई बार जो बात हजारों शब्दों में कहना कठिन होता है, उसे एक प्रभावशाली कार्टून बड़ी सरलता और गहराई के साथ अभिव्यक्त कर देता है। कार्टून समाज को हंसाने के साथ सोचने, समझने और आत्ममंथन के लिए भी प्रेरित करता है।

एआईएडीएमके के 6 विधायकों की अयोग्यता पर 2 महीने में आएगा फैसला

नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर जेसीडी प्रभाकर ने बुधवार को कहा कि मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, विधायकों की अयोग्यता के मामले में दो महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। चेन्नई के पास कुंद्रथुर में एक प्राइवेट कॉलेज में पत्रकारों से बात करते हुए स्पीकर ने बताया कि इस मामले की जांच पहले से ही चल रही है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव की घोषणा के कारण कार्यवाही रोक दी गई थी। तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि अयोग्यता के मामले की जांच अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। प्रभाकर ने साफ़ किया कि दोनों पक्षों यानी शिकायत करने वाले एआईएडीएमके गुटों और जिनका जवाब मांगा गया है।

केजरीवाल की हरी झंडी के बाद कांग्रेस-सीजेपी में दोस्ती

नई दिल्ल। दिल्ली के जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने, छात्रों की गिरफ्तारी और विरोध-प्रदर्शन के अधिकार को लेकर छिड़ा विवाद अब महज कानून-व्यवस्था का मामला नहीं रह गया है। इसके मंच पर देश की सियासत का एक नया नाटक भी आकार लेने लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी पर जिस अंदाज में आवाज बुलंद की है, उससे साफ है कि विपक्ष अब इस आंदोलन को अपने बड़े राजनीतिक अभियान से जोड़ने की कोशिश में है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को अचानक ष्टष्ठक्कके आंदोलन में लोकतंत्र की नई उम्मीद दिखाई देने लगी है, या फिर इसके पीछे चुनाव आयोग, मतदाता सूची और भाजपा के खिलाफ विपक्षी मोर्चे को मजबूत करने की रणनीति काम कर रही है?



राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है और ऐसा करने पर युवाओं को जेल में डालना कायरता है। उन्होंने छात्रों, युवाओं, पत्रकारों और इंडिया गठबंधन का जिक्र करते हुए दावा किया कि अलग-अलग बैनर के बावजूद सबकी लड़ाई संवैधानिक अधिकारों की मांग करना ही है। उनका संदेश था कि जंतर-मंतर जनता का है और उसे वापस हासिल किया जाएगा। देखा जाये तो बात सुनने में दमदार है। आखिर लोकतंत्र में विरोध की आवाज को जगह मिलनी ही चाहिए। लेकिन राजनीति में केवल भाषण नहीं, उसके पीछे की टाइमिंग भी बहुत कुछ कहती है। राहुल गांधी का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीजेपी के आंदोलन को लेकर कांग्रेस का रुख अब तक इतना खुला और स्पष्ट नहीं था। सवाल उठता है कि पहले दूरी, अब दोस्ती क्यों? हम आपको याद दिला दें कि परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ जुलाई में सीजेपी ने जंतर-मंतर पर 17 दिनों तक प्रदर्शन किया था। सोशल मीडिया पर इस संगठन की चर्चा बढ़ी, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने शुरुआत में उससे दूरी बनाए रखी। पार्टी का जोर अपने अभियानों 'छात्रों की गूंज' और 'वोट चोरी पर रहा।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

इंडिया गेट पर पीड़ित परिवार से मिले राहुल-प्रियंका

दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इंडिया गेट जा जाकर अंकिता भंडारी के परिवार से मिले। प्रियंका गांधी भी पहुंची हैं। अंकिता भंडारी के माता-पिता मामले के विरोध में इंडिया गेट पर हैं और वे भाजपा के दुष्यंत गौतम पर



आरोप लगा रहे हैं, जिन्हें हाल ही में सिक्किम का गवर्नर बनाया गया है। महिला कार्यकर्ता योगिता भयाना भी इंडिया गेट पर उनके साथ हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि अंकिता के माता-पिता की ओर से हत्याकांड में शामिल वीआईपी के तौर पर दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिए जाने के बावजूद मामले में सीबीआई जांच नहीं कराई गई। इसके बजाय भाजपा सरकार ने दुष्यंत कुमार गौतम को राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके विरोध में कांग्रेस ने गांधी पार्क में मौन उपवास रखा है।

जयशंकर की नेपाल के गृह मंत्री गुरुंग से मुलाकात

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को नई दिल्ली में नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक की तस्वीरें



सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा करते हुए जयशंकर ने लिखा, नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुंग से मिलकर अच्छा लगा। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब भारत और नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) के पहले गृह मंत्रियों के सम्मेलन से इतर अपने नेपाली समकक्ष सुधन गुरुंग से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई थी।

सीजेपी का दिल्ली के कनॉट प्लेस में शक्ति प्रदर्शन कल

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दिपके ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय ध्वज के साथ इकट्ठा होने का आह्वान किया है। यह कदम पार्टी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका



को हिरासत में लिए जाने के बाद उठाया गया है, जिन्हें जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने के बाद पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो संदेश में, दिपके ने उन लोगों से अपील की जो राष्ट्रीय ध्वज पर गर्व करते हैं कि वे 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे इकट्ठा हों। उन्होंने उन लोगों से भी आग्रह किया जो दिल्ली नहीं आ सकते, कि वे अपने-अपने शहरों में इसी तरह के आयोजन करें। दिपके ने पूछा कि तिरंगा लहराना कब से अपराध हो गया है? उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने को अपराध नहीं माना जाना चाहिए। सेंट्रल पार्क में राष्ट्रीय ध्वज लेकर आएं और हिरासत में लिए गए पार्टी नेताओं के प्रति एकजुटता व्यक्त करें।

लद्दाख में मोदी करेंगे 3350 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वे 15 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और उन्हें देश को



समर्पित करेंगे। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं में लेह के कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट पर नया पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग और निम्मू-पदुम-दारचा रोड शामिल हैं, जो कनेक्टिविटी और रणनीतिक आवाजाही को मज़बूत करेंगे। मोदी ने एक्स पर लिखा कि कल, 15 अक्टूबर को, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लद्दाख में लगभग ?3,350 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और उन्हें देश को समर्पित करूंगा। इनमें शामिल हैं- लेह में कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट पर नया पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग; निम्मू-पदुम-दारचा रोड, जो कनेक्टिविटी और रणनीतिक आवाजाही को बेहतर बनाएगा। इन प्रोजेक्ट्स में 9 एमडब्ल्यू का हनु हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और

ईडी ने रिलायंस पावर की 2000 करोड़ से अधिक संपत्ति जब्त की

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालयने बुधवार को बताया कि उसने अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड की भारत में स्थित 2000 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियां जब्त की हैं। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक जांच का हिस्सा है। जब्त परिसंपत्तियों में आरपीएल के बैंक शेष और सासन पावर लिमिटेड में उसकी शेयरधारिता शामिल है। जब्ती आदेश 12 अक्तूबर को फेमा की धारा 37ए के तहत 2,032.81 करोड़ रुपये का जारी हुआ। कंपनी ने मंगलवार को एक नियामक फाइलिंग में ईडी के आरोपों को विवादित बताया। कंपनी ने कहा कि वह अपने और सभी शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए कानूनी सलाह के अनुसार उचित कदम उठाएगी। ईडी की जांच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की एक कार्रवाई से शुरू हुई थी। यह कार्रवाई आरपीएल द्वारा अपनी लेखा-पुस्तकों में 2,101.46 करोड़ रुपये के बट्टे खाते में डालने या प्रावधानों से संबंधित थी। ये बट्टे खाते में डाले गए धन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्सऔर केमैन आइलैंड्स की कंपनियों में किए गए विदेशी निवेश और अग्रिम से संबंधित थे। रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (जो बाद में आरपीएल में विलय हो गई) ने 2006 में 300 मिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड जुटाए।

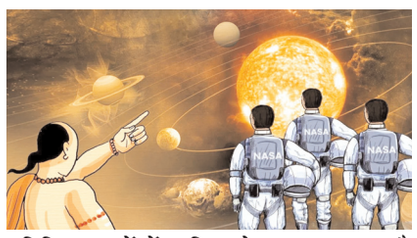
भारतीय ज्ञान

खगोलीय घटनाओं, ग्रहों की गति, मौसम, वर्षा को समझने के लिए ज्ञान-परंपराओं को एक साथ जोड़ा

वराहमिहिर ने आकाश को सिर्फ देखा नहीं उसे गणना में उतारने की कोशिश की

जब दुनिया के पास न टेलिस्कोप था, न कंप्यूटर... न अंतरिक्ष की तस्वीरें थीं... तब क्या कोई इंसान सिर्फ अपनी आंखों, गणना और असाधारण बुद्धि के दम पर आसमान के रहस्यों को समझ सकता था? ज हम मंगल ग्रह पर पानी खोजने के लिए अरबों रुपये के मिशन भेजते हैं। ग्रहों की गति जानने के लिए सुपरकंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन करीब 1500 साल पहले, भारत की धरती पर एक ऐसा विद्वान हुआ, जिसने आकाश को सिर्फ देखा नहीं। उसे गणना में उतारने की कोशिश की। नाम था- वराहमिहिर। गुप्तकाल के उस स्वर्णिम दौर में, जब भारत गणित, खगोल विज्ञान और ज्ञान-विज्ञान की नई ऊंचाइयों को छू रहा था, वराहमिहिर ने खगोलीय घटनाओं, ग्रहों की गति, मौसम, वर्षा और प्रकृति के संकेतों को समझने के लिए अपने समय की उपलब्ध ज्ञान-परंपराओं को एक साथ जोड़ा। उनकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनका ज्ञान नहीं था बल्कि सवाल पूछने का उनका तरीका था। आखिर बिना टेलिस्कोप, बिना कंप्यूटर और बिना आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के वराहमिहिर ने इतना कुछ कैसे समझ लिया था? क्या यह सिर्फ असाधारण गणितीय प्रतिभा थी, या प्राचीन भारत के पास आसमान को पढ़ने की ऐसी कोई वैज्ञानिक परंपरा थी, जिसके बारे में हम आज भी बहुत कम जानते हैं? आज मातृभूमि में खोलेंगे इसी प्राचीन वैज्ञानिक रहस्य की परतें। वराहमिहिर की कहानी- उस जीनियस की, जिसने सदियों पहले आसमान को पढ़ने की कोशिश की थी।

505 ईस्वी में अवंती जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं वहां उनका जन्म हुआ था। असल में उनका मूल नाम सिर्फ मिहिर था। उनके पिता नागावल खुद एक जाने-माने ज्योतिषी थे तो शुरुआती ज्ञान उन्हें वहीं से मिला। लेकिन उन्हें सही दिशा उनके गुरु वराह से मिली। बस इसी अपार ज्ञान और लगन के कारण उनका नाम पड़ गया वराहमिहिर । इसके बाद 550 ईसवी के आसपास वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के

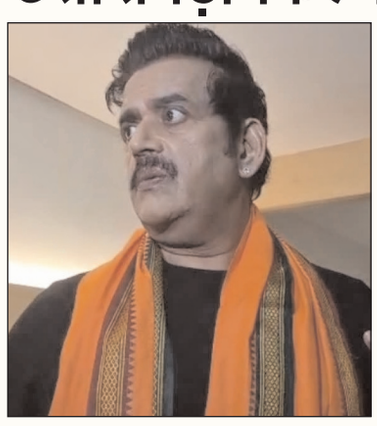


प्रतिष्ठित नवरत्नों में शामिल हो गए। यह बात बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि नवरत्नों का वह समूह कितनी विविधताओं से भरा था। एक तरफ हमारे पास कालिदास हैं जो प्रेम, रोमांस और कला के बिल्कुल शिखर पर थे और ठीक दूसरी तरफ हैं वराहमिहिर जो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक और एक प्योर खगोल शास्त्री थे। मतलब जब एक कवि अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो रहा था। तब दूसरा आसमान में तारों की चाल का सटीक गणित सुलझा रहा था। अब इस नंबर 505 पर गौर करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ उनके जन्म का साल नहीं है। इतिहास में एक बहुत ही रोचक किवदंती दर्ज है कि बचपन में वराह मिहिर की दृष्टि और कुशाग्रता इतनी गजब की थी कि उन्होंने आसमान में एक ही बार में 505 ग्रहों या खगोलीय पिंडों को देख लिया था। हम यहां इसकी साइंटिफिक एक्यूरेसी पर बहस नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह तथ्य साफ बताता है कि उस समय के लोग उनके विजन और उनकी बौद्धिक क्षमता को किस जादुई स्तर का मानते थे। %बृहत् संहिता% वराहमिहिर की सबसे मशहूर रचनाओं में से एक थी। यह वास्तुकला, मंदिरों, ग्रहों की चाल, ग्रहण, समय की गणना, ज्योतिष, मौसम, बादलों के बनने, बारिश, खेती, गणित, रत्न-विज्ञान, इत्र और कई अन्य विषयों पर एक विस्तृत अध्ययन है। वराहमिहिर का कहना है कि हालाँकि उन्होंने खगोल विज्ञान, शिल्प शास्त्र और मंदिर निर्माण पर पहले के कामों का कुछ श्लोकों में सार दिया है, लेकिन डिज़ाइन के कई सिद्धांतों और मॉडलों पर उनकी व्याख्या उन शुरुआती ग्रंथों में से है जो आज भी मौजूद हैं। फ़ारसी यात्री और विद्वान अल-बिरूनी ने बृहत् संहिता के अंशों और वराहमिहिर की बातों का ज़िक्र किया है। इसके अलावा, ज्योतिष और खगोल विज्ञान पर कई प्रतिष्ठित रचनाएँ लिखने का श्रेय भी वराहमिहिर को जाता है। उन्होंने ग्रीक भाषा का अध्ययन किया और अपनी रचनाओं में यूनानियों (यवनों) की तारीफ़ की कि वे विज्ञान में बहुत निपुण थे, भले ही धार्मिक रीति-रिवाजों के मामले में वे अशुद्ध माने जाते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार, राशि-चिह्नों, ज्योतिषीय गणनाओं और शुभ अनुष्ठानों के लिए भविष्यवाणियों को समझने और लोकप्रिय बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है।

रवि किशन का अखिलेश यादव पर हमला, विपक्ष को बताया चुनावी मेंढक, छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करने की जताई इच्छा

बिलासपुर। बिलासपुर के लोग और छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया। इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सरल स्वभाव के हैं और यहां के लोग उनके अपने हैं। छत्तीसगढ़ में उन्हें बहुत प्यार मिलता है। वे कई सालों से यहां आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रेम लगातार मिलता रहा है। यहां उनके बहुत सारे प्रशंसक हैं। ये कहना है एक्टर और राजनेता रवि किशन का। रवि किशन बिलासपुर दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने मीडिया के सामने अपने विचार रखे।इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की चुनौती पर भी पलटवार किया।

अखिलेश यादव ने खुद ये चुनौती दी थी और योगी आदित्यनाथ ने इसे स्वीकार कर लिया है। अब अखिलेश यादव को भी सामने आना चाहिए।और अपनी चुनौती पर कायम रहना चाहिए।उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव देश के बड़े नेता रहे हैं। जब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी और योगी जी ने उसे स्वीकार कर लिया। तो अब उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। देश भी देखना चाहता है कि अखिलेश यादव इस चुनौती पर क्या कदम उठाते हैं। समाजवादी पार्टी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा और भाजपा बड़ी जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव हुए हैं। पहले बिजली के बिल



आते थे, लेकिन बिजली नहीं आती थी। प्रदेश में बाहुबलियों और माफियाओं का प्रभाव था। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। राम की भूमिका को लेकर रवि किशन का कहना है कि वो बहुत डरे हुए हैं, उन्होंने अब तक केवट और परशुराम का किरदार निभाया है। छोटी उम्र में सीता माता की भूमिका भी निभाई थी। लेकिन हमेशा से मन में भगवान राम का किरदार निभाने की इच्छा थी। भगवान राम का रूप धारण करने जा रहे हैं। तो मन में बहुत डर और जिम्मेदारी का एहसास है। प्रार्थना है कि 19 और 20 तारीख को प्रभु राम उनके शरीर में प्रवेश करें। ताकि उनसे कोई गलती न हो। भगवान राम के विचार, वाणी, संयम और त्याग से समाज को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक राजा, पिता और पति के रूप में उनका जीवन सभी के लिए संदेश देता है। रवि किशन ने कहा कि युवा देश की आत्मा हैं। और भविष्य में यही पीढ़ी संसद से लेकर विधानसभा तक देश की जिम्मेदारी संभालेगी। युवा इंजीनियर बनेंगे, सेना में जाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें युवा पीढ़ी से बहुत प्रेम है। उनके घर में भी जेन-जी पीढ़ी का बेटा है, जिससे वे समय-समय पर बहुत कुछ सीखते हैं। रवि किशन ने कहा कि युवाओं को उनकी बातें पसंद आती हैं।क्योंकि वे खुद को भी उन्हीं की तरह एक सामान्य इंसान मानते हैं।उन्होंने कहा, मैं भगवान नहीं हूं, मनुष्य हूं। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक इंसान हूं। उनके मुताबिक, युवाओं को समझने के लिए जरूरी है कि उनकी बातों और विचारों को स्वीकार किया जाए।

अच्छी फिल्में हमेशा दर्शकों के बीच जगह बनाती हैं। छत्तीसगढ़ी सिनेमा में भी काफी संभावनाएं हैं। और इस दिशा में लगातार काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और भोजपुरी भाषाओं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों क्षेत्रों में पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक सोच को महत्व दिया जाता है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी पारिवारिक कहानियों को दर्शकों का समर्थन मिल सकता है। अगर अच्छी कहानियों और मजबूत विषयों पर फिल्में बनाई जाएं।तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा बड़े स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है।

रवि किशन का कहना है कि अगर उन्हें अच्छी कहानी और सही अवसर मिलता है। तो वे छत्तीसगढ़ी सिनेमा में जरूर काम करेंगे। वे कई भाषाओं में काम कर चुके हैं। और छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कहानी होनी चाहिए, जो छत्तीसगढ़ के गौरव, अभियान, भावनाओं और संघर्ष को बड़े स्तर पर सामने लाए। फिल्म में यहां की संस्कृति और लोगों की वास्तविक जिंदगी दिखाई जानी चाहिए। रवि किशन ने कहा कि अगर उन्हें ऐसी मजबूत स्क्रिप्ट मिलती है। तो वे जरूर काम करना चाहेंगे। उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ की कहानी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और राष्ट्रीय पुरस्कार तक पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए।

नाना पाटेकर के निधन को लेकर रवि किशन ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि उनका जाना उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर उन्हें बहुत पसंद करते थे और उनसे काफी प्रेम करते थे।

हालांकि, भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। महादेव की रचना में सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। और मृत्यु पर भी मनुष्य का नियंत्रण नहीं है।

छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय हड़ताल पर तकनीकी सहायक, नियमितीकरण समेत कई मांगें

कांकेर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत वीबी-जी-राम-जी योजना में कार्यरत तकनीकी सहायक तीन दिवसीय हड़ताल पर हैं। नियमितीकरण, नियमित पदों के सृजन और सेवा शर्तों में बदलाव की वे मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।



तकनीकी सहायकों ने चेतावनी दी है कि तीन दिवसीय हड़ताल के बाद भी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। तकनीकी सहायक प्रताप सिंह ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत सभी तकनीकी सहायकों का सीधे संविलियन कर नियमित किया जाना चाहिए। जब तक संविलियन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक पंचायत विभाग में लागू नियमों और सेवा शर्तों के अनुरूप काम लिया जाए। इसके साथ ही तकनीकी सहायक पद का नाम बदलकर कनिष्ठ अभियंता (वीबी-जी-राम-जी) किए जाने की मांग भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कांकेर जिले में लगभग 52 और पूरे छत्तीसगढ़ में 1263 तकनीकी सहायक कार्यरत हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि शासन जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगा। कर्मचारियों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर मजबूरन हड़ताल पर बैठना पड़ा है, 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान 100 दिनों के भीतर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का आश्वासन मिला था। इस संबंध में फाइलें भी आगे बढ़ीं, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। समय पर वेतन नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार कर्ज लेना पड़ता है और दूसरों से आर्थिक मदद मांगनी पड़ती है। बच्चों की स्कूल फीस भरने तक में मुश्किलें आती हैं।--मनीष देवांगन, तकनीकी सहायक तकनीकी सहायक मोनिका साहू ने बताया कि उनके काम का सीधा संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों से है। गांवों में जाकर आवेदन एकत्र करना, मशरूम उत्पादन से जुड़े कार्य, मजदूरों को काम उपलब्ध कराना और उनके कार्यों का मूल्यांकन करना जैसी जिम्मेदारियां तकनीकी सहायकों के पास रहती हैं। ऐसे में तीन दिवसीय हड़ताल से इन कार्यों पर असर पड़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि यदि हड़ताल के बाद भी मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया, तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे।

जोगी पद बना हल्बा समुदाय के लिए मुसीबत

रस्म बंद करने की चेतावनी

जगदलपुर। बस्तर दशहरा पूरे विश्व में अपनी अनोखी सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरे में शामिल होने के लिए देश और दुनियाभर से लोग पहुंचते हैं। बस्तर दशहरा जहां अपनी मजबूत सांस्कृतिक विरासत का परिचय लोगों को देती है, वहीं परंपरा और सामाजिक सदभाव की मिसाल भी पेश करती है। बस्तर दशहरे के दूसरे दिन जोगी बिठाई की अनोखी रस्म निभाई जाती है। इस रस्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। जोगी बिठाई रस्म में जोगी बनकर आमाबाल गांव का युवक 4 फीट गहरे गड्ढे में बैठकर तप करता है। बस्तर दशहरे में जोगी पद की भूमिका निभाने वाले समुदाय के लिए अब यह पद दर्द का सबब बन गया है। दरअसल, जगदलपुर जिला प्रशासन ने इनके परिवार के सभी सदस्यों की जाति में जोगी का उल्लेख कर दिया है। जिससे जोगी पद की भूमिका निभाने वाले समुदाय को काफी दिक्कतों का सामन करना पड़ रहा है। खासकर स्कूली बच्चे और नौकरी की तलाश में रहे युवाओं को। क्योंकि आरक्षण में कटौती होती है और स्कॉलरशिप में भी दिक्क़तें होती हैं। इनकी परेशानी को समाप्त करने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। जिससे नाराज समुदाय के लोग और खुद इस बार जोगी के पद में बैठे युवक दौलत कुमार नाग ने अगले वर्ष समाधान नहीं होने पर इस रस्म को नहीं निभाने की बात कही है। बस्तर



दशहरा समिति के सचिव और तहसीलदार राहुल गुप्ता का कहना है कि जाति के संबंध में उन्हें एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व भी केंद्र सरकार को इन्होंने अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसमें यह बताया गया है शुरू से जोगी के रूप में पूर्वज बिठाते आ रहे हैं, लेकिन उनकी जाति हल्बा है। जोगी उनकी जाति नहीं है बल्कि पद है। इस संबंध में आगे पत्राचार किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द उनकी समस्या दूर हो। बस्तर दशहरा पर्व के निर्विघ्न और शांतिपूर्ण आयोजन की कामना को लेकर यह रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के तहत ग्राम बड़े आमाबाल के हल्बा समुदाय के युवक दौलत कुमार नाग निभाते हैं। 600 सालों से चली आ रही इस परंपरा को लेकर लोगों में बड़ी आस्था है।

एल 1, एल 2 पदों के लिए भर्ती पर फैसला नहीं

दंतेवाड़ा। एनएमडीसी की बचेली परियोजना में स्थानीय युवाओं की भर्ती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एल 1 और एल2 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर 12 ग्राम पंचायतों के बेरोजगार युवाओं का बचेली चेकपोस्ट पर प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। सोमवार सुबह 5 बजे शुरू हुए आंदोलन के चलते परियोजना का कामकाज और उत्पादन प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। भर्ती को लेकर प्रबंधन की ओर से ठोस निर्णय नहीं होने से आंदोलनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।

सोमवार देर रात करीब 1 बजे विधायक चैतराम अटामी की मौजूदगी में एनएमडीसी अधिकारियों और आंदोलनकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में स्थानीय युवाओं की भर्ती से जुड़ी मांगों पर चर्चा की गई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका। इसके बाद आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल को हैदराबाद भेजकर संबंधित अधिकारियों के सामने पक्ष रखने का प्रस्ताव दिया गया था। मंगलवार सुबह आंदोलनकारी इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए।

युवाओं का कहना है कि वे केवल चर्चा के लिए हैदराबाद जाने के बजाय भर्ती



प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में स्पष्ट और ठोस पहल चाहते हैं। उनका सवाल है कि जब स्थानीय युवाओं के रोजगार का मामला लंबे समय से उठाया जा रहा है, तो अब तक इसका समाधान क्यों नहीं निकल पाया है। एनएमडीसी के प्रबंधक हैदराबाद और कहीं बात नहीं किए हैं। वे सोच रहे होंगे कि बिना बात किए इस मामले का हल निकल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होगा। पिछले डेढ़ साल से एल 1 और एल 2 की भर्ती पेंडिंग है। कई दल आकर बात करेंगे तो इसमें और देरी होगी। आंदोलनकारियों के अनुसार, कमेली के सरपंच करन तामो ने बताया कि बैलाडीला दौरे के दौरान एनएमडीसी के सीएमडी कह चुके हैं कि एल 1 और एल2 पदों पर भर्ती प्रक्रिया उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ऐसे में युवाओं का सवाल है कि जब भर्ती का निर्णय सीएमडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो हैदराबाद जाकर चर्चा करने से क्या समाधान निकलेगा?

पीएमजीएसवाय के तहत पर्यावरण और रोजगार दोनों को मिलेगा बढ़ावा

कोरबा। कचरे का प्रबंधन आज एक बड़ी चुनौती के तौर पर देश और दुनिया के सामने है। रोजाना हजारों और लाखों टन कचरा हर शहर की गलियों से निकलता है, और शहर में फैल जाता है। ये कचरा न सिर्फ हवा को जहरीली बनाता है बल्कि बीमारियों को भी बढ़ता है। कचरा प्रबंधन की दिशा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल इसी समस्या को लेकर कोरबा में शुरू की गई है। इसके तहत प्लास्टिक के कचरे से अब सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्लास्टिक के कचरे से बनी सड़कें न सिर्फ टिकाउ होंगी बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी अहम योगदान भी देगी। प्लास्टिक का कचरा सालों साल जमीन पर बना रहता है। इस कचरे के इस्तेमाल से लोगों को और खासकर पर्यावरण को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बनने वाली नई सड़कों के निर्माण में वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग किया जाएगा। इस अनूठी और पर्यावरण के लिए अनुकूल तकनीक के लिए द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस पहल से



न केवल सड़कों की गुणवत्ता और मजबूती में सुधार होगा, बल्कि वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या का भी स्थायी समाधान मिलेगा। कोरबा जिले में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। 15 अक्टूबर के बाद से सड़क निर्माण में गति आएगी। ग्रामीण के साथ ही साथ शहर की सड़कों में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कहा, तकनीक के इस्तेमाल से सड़कों को और अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाया जा सकेगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को अपनाते हुए प्लास्टिक कचरे का रीसायकल कर इसे सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पर्यावरण में फैल रहे प्लास्टिक कचरे के सुरक्षित निपटान में भी बड़ी मदद मिलेगी।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

फेसबुक के जरिए प्रापर्टी डीलर हुआ सायबर फ्रॉड का शिकार

जीपीएम। गौरेला के वार्ड क्रमांक 09, पुराना गौरेला निवासी विशाल जसवाल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। मार्च 2026 में उन्होंने फेसबुक स्क्रोल करने के दौरान sellerstorebuy और esellerstorebuy वेबसाइटों के विज्ञापन देखे। इनमें अधिक लाभ कमाने का प्रलोभन दिया गया था। इसके बाद व्हाट्सएप के जरिए उनसे संपर्क किया गया और ऑनलाइन सामान बेचकर कमाई करने का भरोसा दिलाया। ठगों के कहने पर पीड़ित ने शुरुआत में पांच लाख रुपये जमा किए। इसके बाद उन्हें वर्चुअल खाते में डॉलर के रूप में कमाई होती दिखाई गई। जब उन्होंने यह रकम अपने वास्तविक बैंक खाते में लेने की कोशिश की, तो ठगों ने अतिरिक्त शुल्क जमा करने की बात कही। मुनाफा मिलने की उम्मीद में वह पैसे जमा करते रहे और अंतत: 7.90 लाख रुपये गंवा बैठे। पीड़ित पहले अपने स्तर से काफी प्रयास किया कि पैसा मिले पर जब चारों ओर से हाथ खाली होने पर 11 अक्टूबर को गौरेला थाने आकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। जिस पर पुलिस मोबाइल नंबरों के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

चोरों का तांडव! एक महीने में आधा दर्जन से अधिक वारदातें

तखतपुर। जिले के तखतपुर क्षेत्र में चोरी की लगातार हो रही घटनाओं से व्यापारियों और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। पिछले एक महीने के भीतर आधा दर्जन से अधिक चोरी की वारदातें सामने आने आई हैं। वहीं बीते तीन दिनों के भीतर दो किराना दुकानों को निशाना बनाया गया है। लगातार हो रही इन घटनाओं से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक, जरोंधा के साहू किराना स्टोर में आज चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस दुकान में तीन महीने के भीतर दूसरी बार चोरी हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद अज्ञात चोर मौके पर अपनी टोपी और गमछा छोड़कर फरार हो गए। त्योहारी सीजन में लगातार दूसरी बार दुकान में चोरी होने से दुकानदार की परेशानी बढ़ गई है। पिछली वारदात में अबतक पुलिस जांच जारी है। मोढ़े मार्ग पर बेलसरी के पास स्थित महामाया किराना स्टोर में 11 अक्टूबर को चोरी हुई थी। आरोप है कि चोर दुकान से नकदी और किराना सामान समेत करीब 95 हजार रुपये का माल लेकर फरार हो गए।

बिलासपुर का एक्सक्लूसिव 'सफेद शहरी गरबा' बना यादगार

बिलासपुर। डब्ल्यू. ई. (वोमेन इंट्रस्ट) द्वारा आयोजित एक्सक्लूसिव 'सफेद शहरी गरबा' बेहद भव्यता और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। सीमित प्रतिभागियों के लिए आयोजित इस विशेष गरबा संध्या में महिलाओं ने संगीत, नृत्य, स्वादिष्ट व्यंजनों और मनोरंजक गतिविधियों का भरपूर आनंद लिया। नवरात्रि के उल्लास से सराबोर इस शाम में सभी महिलाएं खूबसूरत सफेद परिधानों में सजी नजर आईं, जिसने पूरे आयोजन को एक आकर्षक और खास पहचान दी। कार्यक्रम का आयोजन सोनल अग्रवाल और रुचि अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया, जबकि शिल्पा शाह और आद्या अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। आयोजन की शानदार सजावट, बेहतरीन व्यवस्थाओं और अनूठी थीम ने सभी का दिल जीत लिया। उपस्थित महिलाओं ने सोनल अग्रवाल और रुचि अग्रवाल की आयोजन क्षमता, खूबसूरत डेकोर और व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की। सभी ने डब्ल्यूई बिलासपुर का आभार व्यक्त करते हुए इतने शानदार और यादगार आयोजन के लिए संस्था की प्रशंसा की।

रतनजोत के बीज खाने से 7 बच्चे बीमार, स्कूल पर लगे आरोप

कांकेर। जिले के पखांजूर क्षेत्र के माटोली गांव स्थित प्राथमिक शाला में रतनजोत के बीज खाने से सात बच्चे बीमार हो गए। बच्चों ने स्कूल समय के दौरान रतनजोत के बीज खा लिए थे। घर पहुंचने के बाद एक-एक कर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। घर में बच्चों को बार बार उलटी करता देख परिजन घबरा गए और बच्चों को लेकर तुरंत पखांजूर सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सभी सात बच्चों का इलाज जारी है। घटना के बाद से परिजनों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले भी रतनजोत के बीज खाने से बच्चे बीमार हो चुके हैं। इसके बावजूद बच्चों की सुरक्षा को लेकर जरूरी सतर्कता नहीं बरती गई। ग्राम पंचायत की सरपंच सुखबत्ती मरकाम सहित ग्रामीणों ने मामले में जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्कूल के समय में टीचर पर बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी होती है।

कोयला और राखड़ परिवहन के खिलाफ आंदोलन

सूरजपुर। विश्रामपुर इलाके में नियमों के खिलाफ जाकर कोयला और राखड़ परिवहन किए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने की है। स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि तय मानकों को दरकिनार कर कोयला और राखड़ का परिवहन कॉलोनी के पास से किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने पहले इसके खिलाफ आंदोलन किया, जिसके बाद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस आंदोलन और चक्काजाम में शामिल हो गए। नाराज लोगों ने कोयला और राखड़ परिवहन कॉलोनी के पास से किए जाने के खिलाफ चक्काजाम कर दिया। चक्काजाम किए जाने की खबर जैसे ही जिला प्रशासन की टीम को मिली, तुरंत ही मौके पर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचीं। नायब तहसीलदार ने सड़क पर बैठे लोगों को समझाने की हर संभव कोशिश की। लेकिन नाराज ग्रामीणों और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि जबतक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तबतक आंदोलन जारी रहेगा।

कांकेर में अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग, यातायात पुलिस का एक्शन

कांकेर। कांकेर शहर में लगातार लग रहे जाम और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने यातायात पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। कोतवाली थाना के सामने से शुरू हुई कार्रवाई पुल से लेकर ऊपर-नीचे रोड तक की गई। इस दौरान दुकानों के बाहर सामान रखने वाले दुकानदारों, सड़क किनारे निर्माण सामग्री रखने वालों और यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों और नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को लॉक किया गया। वहीं दुकानदारों को अपना सामान दुकान के भीतर रखने और वाहन चालकों को सफेद पट्टी के अंदर ही पार्किंग करने की समझाइश



यातायात पुलिस का एक्शन, 156 लोगों को नोटिस कांकेर में अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग को लेकर यातायात विभाग ने कार्रवाई की है.

दी गई।

यातायात प्रभारी दीपक साव ने बताया कि पिछले सप्ताह चलाए गए अभियान के दौरान 104 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे।वहीं, आज की कार्रवाई में 52 लोगों को नोटिस दिया गया है। त्योहार और बाजार के कारण शहर में लोगों की भीड़ बढ़ने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। नो पार्किंग में खड़ी बाइक और अन्य वाहनों के कारण भी आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं, मस्जिद के पास सड़क किनारे बड़ी संख्या में सब्जी के पसरे लगने से भी यातायात बाधित हो रहा है।इसे देखते हुए नगर पालिका और यातायात पुलिस की टीम ने सब्जी विक्रेताओं को सड़क से दूर पसरा लगाने की समझाईश दी, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की ओर से पैदल पेट्रोलिंग भी की जा रही है। यातायात पुलिस के अनुसार, शहर में अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। गुरुवार को पुल से ज्ञानी चौक तक और शहर के अन्य क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा। पुलिस ने दुकानदारों और वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने तथा सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने की अपील की है

सड़क पर बैठे दिव्यांग बच्चों की भर आई आंखें, समाज कल्याण विभाग का अपना दावा

जगदलपुर। आड़ावाल में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए शासन की ओर से स्कूल खोला गया है। शासन की कोशिश है कि जो बच्चे देख, सुन और बोल नहीं सकते, उन बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले ताकि वो अपना बेहतर भविष्य गढ़ सकें। लेकिन शासन की इस मंशा पर अब यहां पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि उनका स्कूल लंबे वक्त से शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। शिक्षकों की कमी के चलते उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर किए जाने की मांग को लेकर, मंगलवार को दिव्यांग छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि जब भी वो स्कूल में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाते हैं, तो उनको स्कूल से बाहर निकालने या फिर टीसी देने की धमकी जिम्मेदारों की ओर से दी जाती है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि अगर उनकी पढ़ाई शिक्षकों की कमी से प्रभावित हो रही है, तो उनका ये हक है कि वो अपनी



जायज मांगों को स्कूल प्रबंधन के सामने रखें। छात्रों का आरोप है कि जब भी वो अपनी मांगें स्कूल प्रबंधन के सामने रखते हैं, उनको स्कूल से टीसी देने की धमकी देकर चुप करा दिया जाता है। हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है। हम चाहते हैं कि स्कूल में शिक्षकों की कमी को समय रहते दूर किया जाए। लंबे वक्त से हम लोग स्कूल प्रबंधन से इस बात को लेकर शिकायत भी कर रहे हैं। पहले तो हमारी बातों को स्कूल प्रबंधन ने अनसुना कर दिया, फिर जब हमने दोबारा शिकायत दी तो हमें स्कूल से निकालने और टीसी देने की धमकी दी जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

27 को होगी साय कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय



की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को साय कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक मंत्रालय महानदी भवन में होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के साथ फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में धान खरीदी को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। धान खरीदी का सीजन नजदीक आने के साथ ही किसानों और कृषि से जुड़े मुद्दे अहम हो गए हैं। ऐसे में कैबिनेट की इस बैठक पर किसानों सहित प्रदेशभर की नजरें टिकी रहेंगी। इसके अलावा बैठक में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, प्रशासनिक विषयों और जनहित से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मिलेट फसलों के उपार्जन, उत्पादन के संबंध में बैठक

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की



अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कोदो, कुटकी, रागी तथा मक्का के उपार्जन एवं फसल विविधीकरण, किसानों को प्रोत्साहित करने सहित अन्य आवश्यक विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में इन कृषि उत्पादों की आवश्यकता, उपार्जन तथा मिलेटस के उपयोग के संबंध में चर्चा हुई। इसके तहत स्कूलों में मध्यांह भोजन और महिला एवं बाल विकास के पोषक आहार कार्यक्रमों में आंगनबाडियों के माध्यम में वितरित करने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

राज्यपाल ने की विशेष ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता इभानन साहू की सराहना

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से आज



लोकभवन में विशेष ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता इभानन साहू ने मुलाकात की। ऑटिज्म से प्रभावित आकांक्षा लायंस इंस्टिट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट रायपुर के इस 22 वर्षीय छात्र ने हांगकांग में आयोजित स्पेशल ओलंपिक ईस्ट एशिया रीजनल बॉलिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किया है। राज्यपाल ने इभानन साहू की उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी और उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की पहल की। डेका ने कहा कि इभानन साहू की उपलब्धि अदम्य इच्छाशक्ति और कठोर परिश्रम का प्रेरणादायी उदाहरण है। उनकी सफलता न केवल छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। राज्यपाल ने आकांक्षा लायंस इंस्टिट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट रायपुर द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने संस्था के शैक्षणिक कार्यो को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपने स्वेच्छानुदान मद से 10 कम्प्यूटर प्रदान करने की बात कही। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष डॉ. नितिन धबलिया, निदेशक डॉ. साधना नायक, प्राचार्य श्रीमती प्रतिष्ठा शुक्ला, एच.एफ.ओ. नित्यानंद जैसवाल, इभानन की माता श्रीमती तेजश्री साहू एवं अन्य शिक्षक उपस्थित थे।

भैयाथान में 5.50 किलोमीटर सड़क निर्माण को मिली स्वीकृति

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की पहल और प्रयासों से सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड में सड़क निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य स्वीकृत हुआ है। राज्य शासन ने तेलगांव मुख्य मार्ग से बरपारा होते हुए बुंदिया चौक तक 5.50 किलोमीटर लंबाई की सड़क के निर्माण के लिए 543.67 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि लगभग 5 करोड़ 43 लाख 67 हजार रूपये है। यह कार्य वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल है। लोक निर्माण विभाग के आदेश के अनुसार निर्माण के लिए आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय सहमति के बाद स्वीकृति जारी की गई है। कार्य को तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा और इसकी निविदा प्रमुख अभियंता कार्यालय में गठित निविदा प्रकोष्ठ के माध्यम से कराई जाएगी। स्वीकृति आदेश में निर्माण की गुणवत्ता, पारदर्शी निविदा प्रक्रिया और निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करने पर जोर दिया गया है। स्वीकृत राशि की सीमा में ही व्यय सुनिश्चित करने तथा कार्य के प्राक्कलन और निष्पादन में मितव्ययिता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। निर्माण कार्य में किसी स्तर पर गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। स्वीकृत इस सड़क से तेलगांव मुख्य मार्ग, बरपारा और बुंदिया चौक के बीच संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है।

कार्टून समाज को जागरूक करने के साथ आत्ममंथन के लिए करता है प्रेरित : साय

मुख्यमंत्री कार्टून फेस्टिवल-2026 में हुए शामिल, कार्टून वॉच पत्रिका के 30 वर्ष पूर्ण होने पर दी बधाई

रायपुर। कार्टून केवल हास्य और मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतंत्र और समाज का सशक्त दर्पण है। यह गंभीर विषयों, सामाजिक परिस्थितियों और विसंगतियों को हास्य एवं व्यंग्य के माध्यम से सहजता से जनमानस तक पहुंचाने वाली प्रभावशाली रचनात्मक विधा है। कई बार जो बात हजारों शब्दों में कहना कठिन होता है, उसे एक प्रभावशाली कार्टून बड़ी सरलता और गहराई के साथ अभिव्यक्त कर देता है। कार्टून समाज को हंसाने के साथ सोचने, समझने और आत्ममंथन के लिए भी प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में कार्टून वॉच पत्रिका द्वारा आयोजित कार्टून फेस्टिवल-2026 को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कला और साहित्य किसी भी समाज की चेतना के वाहक होते हैं। कार्टून इस दृष्टि से विशिष्ट कला है, जिसमें चित्र, विचार, हास्य और व्यंग्य का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। एक कार्टूनिस्ट अपने सूक्ष्म अवलोकन और रचनात्मक दृष्टि से सामाजिक घटनाओं को ऐसा स्वरूप देता है, जो लंबे समय तक लोगों की स्मृति में बना रहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्टून जनभावनाओं,



जनअपेक्षाओं और सामाजिक सरोकारों को अभिव्यक्ति देने का भी सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने भारतीय कार्टून कला की समृद्ध परंपरा का उल्लेख करते हुए महान कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के योगदान को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि आर.के. लक्ष्मण का प्रसिद्ध कॉमन मैन केवल एक कार्टून चरित्र नहीं, बल्कि देश के सामान्य नागरिक की आशाओं, अपेक्षाओं, जिज्ञासाओं और चिंताओं की पहचान बन गया। स्वतंत्रता के बाद बदलते भारत और उसकी सामाजिक परिस्थितियों को उन्होंने जिस प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया, वह भारतीय पत्रकारिता और कार्टून कला की अमूल्य विरासत है।

साय ने बस्तर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्टून कला को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे दूरस्थ अंचलों की प्रतिभाओं को भी अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने और इस विधा से जुडने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कार्टून फेस्टिवल-2026 में जयपुर के प्रख्यात कार्टूनिस्ट अभिषेक तिवारी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी कलाकार की दीर्घकालीन साधना और रचनात्मक योगदान का सम्मान पूरी कला विधा का सम्मान है और इससे नई पीढ़ी को उत्कृष्टता की ओर बढने की प्रेरणा मिलती है।

मुख्यमंत्री ने युवा कार्टूनिस्टों का आह्वान करते हुए कहा कि नई पीढ़ी में प्रतिभा, कल्पनाशीलता और तकनीक की अपार संभावनाएं हैं। डिजिटल माध्यमों के विस्तार ने रचनात्मक अभिव्यक्ति के नए मंच उपलब्ध कराए हैं। युवा कलाकार अपनी मौलिकता और रचनात्मक दृष्टि को बनाए रखते हुए इन अवसरों का उपयोग करें और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान अपनी समृद्ध कला, संस्कृति, साहित्य और रचनात्मक परंपराओं से है। राज्य सरकार इनके संरक्षण एवं संवर्धन के साथ कलाकारों और रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्टून फेस्टिवल जैसे आयोजन स्थापित कलाकारों के अनुभव और युवा प्रतिभाओं की ऊर्जा को एक मंच पर लाकर कला एवं समाज के बीच रचनात्मक संवाद को मजबूत करते हैं।

कार्यक्रम के दौरान सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व, नेतृत्व और सेवा यात्रा पर आधारित कार्टून कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि कार्टून के माध्यम से किसी व्यक्तित्व और उसकी यात्रा को प्रस्तुत करना अभिव्यक्ति का विशिष्ट और रोचक माध्यम है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्टून वॉच पत्रिका के प्रकाशन के 30 वर्ष पूर्ण होने और 31वें वर्ष में प्रवेश करने पर पत्रिका के संपादक श्री त्र्यंबक शर्मा सहित पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि तीन दशकों तक कार्टून जैसी विशिष्ट रचनात्मक विधा को समर्पित पत्रिका का निरंतर प्रकाशन उल्लेखनीय उपलब्धि है। कार्टून वॉच ने इस कला के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ देशभर के स्थापित और नवोदित कार्टूनिस्टों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए सशक्त मंच उपलब्ध कराया है।

लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कार्टून के माध्यम से समाज के गंभीर और संवेदनशील विषयों को व्यंग्य के जरिए सहज एवं सरल रूप में रेखांकित किया जा सकता है। उन्होंने कार्टून कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए श्री त्र्यंबक शर्मा के प्रयासों की सराहना करते हुए कार्टून वॉच पत्रिका के 30 वर्ष पूर्ण होने पर पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री साय ने कार्टून फेस्टिवल-2026 के सफल आयोजन के लिए आयोजकों, सहयोगियों, कार्टूनिस्टों और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के साथ समाज में सकारात्मक और विचारशील संवाद को और समृद्ध करेंगे। कार्यक्रम में कार्टून वॉच के संपादक श्री त्र्यंबक शर्मा, श्री हिमांशु द्विवेदी सहित जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ पत्रकार, देश के विभिन्न हिस्सों से आए कार्टूनिस्ट, कलाकार तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

विजय शर्मा ने कवर्धा में मां महामाया के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने बुधवार को नवरात्रि के अवसर पर कबीरधाम जिले के विभिन्न देवी मंदिरों में दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और कल्याण की कामना की। उन्होंने कवर्धा स्थित प्रसिद्ध मां महामाया मंदिर और मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद लिया। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सर्वप्रथम मां महामाया मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन किए और विधिवत पूजा-अर्चना की। इसके पश्चात उन्होंने मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन कर प्रदेश एवं कबीरधाम जिले की सुख-शांति, समृद्धि और निरंतर प्रगति की कामना की।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में निर्माणाधीन ज्योति कलश भवन का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।



उन्होंने भवन निर्माण से जुड़ी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। ज्योति कलश भवन के निर्माण से मंदिर परिसर में धार्मिक आयोजनों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार में सहायता मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कवर्धा के छिरपानी कॉलोनी स्थित मां दुर्गा पंडाल पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर क्षेत्रवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की।

बस किराया बढ़ोतरी और भर्ती परीक्षाओं पर सियासत

महंगाई से लोग त्रस्त : भूपेश बघेल

■ **बैज ने परीक्षा प्रणाली को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बस किराए में बढ़ोतरी और सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस किराया बढ़ाए जाने को लेकर सरकार को घेरा, वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे भ्रष्टाचार का अड्डा करार दिया।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस किराए में बढ़ोतरी को लेकर कहा कि प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे लोग त्रस्त हैं। बिजली बिल में तीन साल के भीतर पांच बार बढ़ोतरी की जा चुकी है, जबकि बस किराया एक साल में दूसरी बार बढ़ाया गया है। इस बार बस किराए में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का भी मुद्दा उठाया। भूपेश



बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। अब क्या बचा है, जिसके दाम नहीं बढ़े हैं।

सरकारी भर्ती परीक्षाओं और पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कभी इंटरव्यू स्थगित हो जाता है, कभी प्रमोशन और कभी परीक्षा स्थगित कर दी जाती है। बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार देश और प्रदेश में परीक्षाएं ठीक से आयोजित नहीं कर पा रही है। भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार आ रही बाधाओं से अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसी भी विभाग की परीक्षा सुरक्षित नहीं है। उन्होंने पुलिस भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू स्थगित होने और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल उठाए। बैज ने कहा कि भाजपा सरकार ने दावा किया था कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) की परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तर्ज पर आयोजित की जाएगी, लेकिन सरकार शिक्षक भर्ती, व्यापम और सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती जैसी परीक्षाएं भी ठीक से नहीं करवा पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की परीक्षा प्रणाली को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है।

छत्तीसगढ़ की लोककलाओं को डिजिटल माध्यमों से दुनिया तक पहुंचाएं : डेका

रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोककलाओं जैसे पंडवानी, पंथी, राउत नाचा, सुवा नृत्य, कर्मा और बस्तर की जनजातीय नृत्य परंपराओं का जिक्र करते हुए उन्होंने जोर दिया कि प्रदेश की इस सांस्कृतिक थाती को मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से देश-विदेश के कोने-कोने तक पहुंचाया जाना चाहिए। राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय का 70वां स्थापना दिवस समारोह राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की 70 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के सामूहिक योगदान का परिणाम बताया।

राज्यपाल श्री डेका ने दानवीर राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती द्वारा अपनी पुत्री राजकुमारी इंदिरा सिंह की स्मृति में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दिए गए ऐतिहासिक योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि संगीत मनुष्य को मानसिक शांति प्रदान करता है, जबकि नृत्य, चित्रकला और शिल्प समाज के इतिहास व संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि कला के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए प्रतिभा के साथ-साथ धैर्य, निरंतर अभ्यास और समर्पण बहुत जरूरी है। साथ ही, उन्होंने कला को आजीविका और व्यवसाय से जोडने की



संभावनाओं पर भी बल दिया।

सांसद श्री संतोष पांडे ने कहा कि राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती द्वारा अपनी पुत्री की स्मृति में दिया गया दान अद्वितीय और अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जमीन दान करना भी कठिन है, लेकिन राजपरिवार की दूरदर्शी सोच ने खैरागढ़ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। उन्होंने शिक्षा, कला-कौशल, परिश्रम और राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करने का संदेश भी दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत में स्वागत उद्बोधन विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. लवली शर्मा ने दिया। इस गरिमापूर्ण आयोजन में राजपरिवार की सदस्य राजकुमारी शताक्षी सिंह, सांसद प्रतिनिधि भागवत शरण सिंह, प्रभारी कुलसचिव आर. वेंकट रमण गुड़े, जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में प्राध्यापक, विद्यार्थी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

वरिष्ठ डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री से मिला, लंबित मांगों से कराया अवगत

रायपुर। वरिष्ठ डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की और अपनी लंबित मांगों के संदर्भ मे बात रखी,जिसमें एक प्रमुख आयुष्मान भारत की बकाया राशि का अस्पतालों को भुगतान करने का निर्देश दिया,और भी विषयों पर उन्होने जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में आईएमए छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ अनूप वर्मा एवं आईएमए रायपुर के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. केतन शाह, सेक्रेटरी डॉ. संजीव श्रीवास्तव, आईएमए बिल्डिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. कमलेश्वर अग्रवाल तथा हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेंद शुक्ला एवं सेक्रेटरी डॉ. गंभीर सिंह शामिल थे।

मंत्री को अवगत कराया गया कि ऐसे प्रशासनिक पद जो की डॉक्टर्स के लिए ही स्वीकृत हैं वहां पर आईएएस अफसरों की नियुक्ति की जा रही है , यदि इन पदों पर डाक्टर्स की नियुक्ति होती तो डॉक्टर्स तथा हॉस्पिटल्स में होने वाली समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता से किया जा सकता।



आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले तकरीबन 10 वर्षों में भुगतान की दरों में वृद्धि ना होने तथा भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी ना होने की वजह से तथा इतने वर्षों में अस्पतालों के क्रय में अत्यधिक वृद्धि होने की वजह से अस्पतालों को ग़लत रास्ते लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, इन विसंगतियों को उत्पन्न ही ना होने देने के लिए सरकार को तुरंत क़दम उठाने का आग्रह किया गया है।

जिन अस्पतालों पर एक निजी समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित किए जाने से जाँच व कार्यवाही की जा रही है, वह जाँच निष्पक्षता से हो तथा उनको अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। डॉक्टर्स व अस्पतालों पर नर्सिंग होम एक्ट के लगने के बाद क्लीनिक्स, छोटे, मंझोले तथा बड़े अस्पतालों व प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को बराबर की कसौटी पर रखा गया है , इससे सबसे ज़्यादा 50 बिस्तरों से कम वाले हॉस्पिटल व क्लीनिक्स हैं , आप से आग्रह है की ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के तहत इन अस्पतालों पर नियमों में राहत दी जाए। सभी प्रकरणों के लाइसेंस एवं निराकरण सिंगल विंडो के माध्यम से होना है , सरकार इस पर काफ़ी आगे बढ़ भी चुकी है किंतु इसका मसौदा आईएमए से भी साझा करें ताकि इसमें आने वाली परेशानियों को पहले ही दूर किया जा सके। अग्निशमन विभाग से एनओसी की समस्याएँ लगातार बढ़ती ही जा रही है तथा इस संबंध में कई बार अधिकारियों व आप के समक्ष अपना पक्ष रखा जाता रहा है।क्लिनिक , छोटे अस्पताल जो की ग्राउंड प्लस प्रथम तल पर संचालित हो रहे हैं उन्हें नियमों के तहत भी पूर्ण राहत दी जा सकती है। बायोमेडिकल वेस्ट की कंपनी एसएमएस वाटरग्रेस एन्वायरोप्रोटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जबरन तक़रीबन 4-5 गुना वसूली लगातार कई वर्षों से और वह भी वार्षिक बढ़ोतरी के क्रम में किए जा रही है। उन्हें तर्कसंगत व वजन के हिसाब से भुगतान लेने के लिए बाध्य किया जाए तथा इस समस्या का त्वरित निराकरण अत्यंत ही आवश्यक है।

विकास अनुज्ञा निरस्त होने पर रेरा ने की सौराष्ट्र रियल एस्टेट परियोजना का पंजीयन किया निरस्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, नियमों का पालन और घर एवं भूखंड खरीदारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने बिलासपुर जिले में स्थित रियल एस्टेट परियोजना सौराष्ट्र की स्वीकृत विकास अनुज्ञा निरस्त होने के बाद परियोजना का रेरा पंजीयन भी निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर की गई है।

प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रमोटर श्री नमन गोयल द्वारा विकसित की जा रही सौराष्ट्र परियोजना बिलासपुर जिले के अग्रय नगर, वार्ड क्रमांक 12, खसरा नंबर 1551 में स्थित है। यह परियोजना सीजी रेरा में पंजीयन क्रमांक पीसीजीआरईए61025001981 के अंतर्गत पंजीकृत थी। परियोजना को संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास



नियम, 1984 के नियम 25 के अंतर्गत विकास अनुज्ञा प्रदान की गई थी। संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना की स्वीकृत विकास अनुमति निरस्त किए जाने के बाद सीजी रेरा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वत: संज्ञान लिया और नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की।

प्रकरण की समीक्षा के उपरांत प्राधिकरण ने 05 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में स्पष्ट किया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास अनुज्ञा निरस्त किए जाने के कारण परियोजना का रेरा पंजीयन जारी रखना उचित नहीं है। इसी आधार पर प्राधिकरण ने सौराष्ट्र परियोजना का पंजीयन निरस्त करने का निर्णय लिया। सीजी रेरा की यह कार्रवाई स्पष्ट करती है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के संचालन में वैधानिक अनुमतियों और निर्धारित नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। परियोजनाओं के पंजीयन के साथ-साथ उनकी विकास अनुमतियों की वैधता भी महत्वपूर्ण है। प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार के मामलों में कार्रवाई से रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयासों को मजबूती मिल रही है।

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने आम नागरिकों, भूखंड खरीदारों एवं संभावित निवेशकों से अपील की है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने अथवा भूखंड, मकान या फ्लैट खरीदने से पहले संबंधित परियोजना के रेरा पंजीयन की वर्तमान स्थिति, स्वीकृत विकास अनुमति तथा अन्य आवश्यक अनुमतियों की जांच अवश्य करें।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
Ph. No. 07741-232068 Email ID-ee-res.kawardha@nic.in

क्रमांक/1980/निविदा/ग्रा.या. सेवा/2026-27 कबीरधाम दिनांक 13/10/2026

संक्षिप्त ई-निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 04. (प्रथम आमंत्रण)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत (लोक निर्माण विभाग में) "द" एवं उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्न दर्शित विकासखण्ड अन्तर्गत छोटे-छोटे रु. 30.00 लाख लागत तक के विभिन्न निर्माण कार्यो का जोनल निविदा (30 लाख तक) के निर्माण कार्य हेतु दिनांक 29.10.2026 तक ऑनलाइन जोनल ई- निविदा आमंत्रित की जाती है।

स. क्र.	कार्य का विवरण	प्रत्येक भाग की अनुमानित लागत (रू. लाख में)
1.	जोनल निविदा वि.ख. कवर्धा भाग - 03, 04 (कुल 02)	30.00
2.	जोनल निविदा वि.ख. बोड़ला भाग - 03, 04 (कुल 02)	30.00

उपरोक्त निर्माण कार्यो की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट में https://eproc.cgstate.gov.in में अथवा कार्यायलीन अवधि में कार्यालय में उपस्थिति होकर दिनांक 15.10.2026 से देखी जा सकती है।

(सुरेन्द्र कुमार पटेल)
कार्यपालन अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

जी-262703969/5

यूपी में अखिलेश के लिए बना सरदर्द ओवैसी

नीरज कुमार दुबे

उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का चुनाव अभी कुछ समय दूर है, लेकिन शह-मात का खेल अभी से गरमाने लगा है। समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर गठबंधन की उम्मीद लेकर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी को जब अखिलेश यादव ने भाव नहीं दिया, तो एआईएमआईएम प्रमुख ने आजमगढ़ की धरती से ऐसा सियासी तीर छोड़ा, जिसका निशाना सीधे लाल टोपी और मुलायम-अखिलेश की मुस्लिम राजनीति पर जा लगा। ओवैसी ने मुसलमानों से यादव परिवार की 'गुलामी' छोड़कर अपनी सियासी रहनुमाई खुद करने का आह्वान कर दिया। यानी गठबंधन की मेज पर जगह नहीं मिली, तो अब सियासी मैदान में हिस्सेदारी का हिसाब मांगा जाएगा! देखा जाये तो ओवैसी का हमला महज जुबानी जंग नहीं, बल्कि उस मुस्लिम वोट बैंक पर दावेदारी की खुली घोषणा है, जिसे समाजवादी पार्टी लंबे समय से अपनी सियासी ताकत का अहम हिस्सा मानती रही है। ओवैसी का आरोप है कि मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक, मुस्लिम समाज ने पीढ़ियों तक सपा का साथ दिया, लेकिन बदले में उसे अपने दम पर नेतृत्व खड़ा करने का पर्याप्त मौका नहीं मिला। ओवैसी का सवाल साफ है कि अगर वोट मुसलमानों का, मेहनत मुसलमानों की और सत्ता की सीढ़ी मुसलमानों के समर्थन से तैयार होती है, तो फिर नेतृत्व के दरवाजे पर ताला क्यों? यही वह सवाल है, जो अखिलेश यादव के लिए सियासी सिरदर्द बन सकता है। क्योंकि यूपी की राजनीति में वोट का गणित सिर्फ जातियों की गिनती से नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी से भी तय होता है। ओवैसी इसी हिस्सेदारी के मुद्दे को हथियार बनाकर सपा के उस मजबूत सामाजिक समीकरण में सेंध लगाने की तैयारी में हैं, जिसके सहारे अखिलेश 2027 में बीजेपी को चुनौती देने का सपना देख रहे हैं। साथ ही आजमगढ़ को लेकर ओवैसी ने अखिलेश को घेरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। शिब्ली नेशनल कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा न मिलने, शिब्ली अकादमी को कथित तौर पर महज पांच लाख रुपये देने, खराब सड़कों, बंद पड़े हवाई अड्डे और महंगी शिक्षा का सवाल उठाकर उन्होंने सपा के विकास के दावों पर चोट की। साथ ही उन्होंने यह भी तंज कसा कि जब आजमगढ़ में सपा के दो सांसद, दस विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष तक पार्टी के हैं, तो जमीन पर विकास की तस्वीर इतनी बदहाल क्यों है? देखा जाये तो सवाल स्थानीय है, लेकिन निशाना सीधे अखिलेश की सियासी साख पर है। उधर, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती पर ओवैसी ने दोनों को क्रमशः संभल और गोरखपुर से उतरने की नसीहत देकर राजनीतिक अखाड़े में नया दांव चल दिया। साथ ही मोदी और योगी सरकार पर मुठभेड़ों, बुलडोजर कार्रवाई और मुसलमानों के घरों-दुकानों पर कार्रवाई को लेकर हमला बोलते हुए उन्होंने खुद को मुस्लिम अधिकारों की मुखर आवाज के रूप में पेश किया। लेकिन इस पूरी लड़ाई का असली सवाल यही है कि क्या ओवैसी मुस्लिम समाज के भीतर स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व खड़ा कर पाएंगे, या उनका वोट काटने वाला चेहरा होने का आरोप ही उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बनेगा? इसमें कोई दो राय नहीं कि सपा के साथ गठबंधन की कोशिश नाकाम होने के बाद ओवैसी के सामने अपनी ताकत साबित करने की चुनौती है। वहीं अखिलेश के सामने यह भरोसा कायम रखने की परीक्षा है कि उनका सामाजिक गठबंधन सिर्फ चुनाव जीतने का समीकरण नहीं, बल्कि सत्ता में भागीदारी का भी रास्ता है। देखा जाये तो यूपी में 2027 की जंग अभी शुरू नहीं हुई है, मगर मुस्लिम वोटों की चौसर बिछ चुकी है। ओवैसी ने चाल चल दी है।

तीसरे कार्यकाल के तीसरे वर्ष में मोदी के सामने चुनौतियों का पहाड़

शेखर गुप्ता



यह नरेंद्र मोदी के सत्ता में 25 वर्षों के साथ ही उनके आगे के सफर को देखने का समय है। उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल ने उनकी तारीफ करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। बेशक आलोचक भी मैदान में हैं और वे सार्वजनिक जीवन में उनके एक चौथाई सदी के सफर की चीर-फाड़ कर रहे हैं, वह भी शल्यचिकित्सक के चाकू से नहीं बल्कि हंसिए से।

यह पत्रकारों सहित तमाम लोगों के लिए यह बताने का भी मौका है कि 'जब मैं पहली बार मोदी से मिला।' बहरहाल, मैं इस बारे में अपनी कहानी किसी और दिन के लिए बचाकर रखूंगा। हाल में इस स्तंभ में मैंने लिखा था कि भारत में किसी भी सत्तारूढ़ नेता के लिए कार्यकाल का तीसरा साल सबसे कठिन होता है।

इसी दौरान चुनौतियां बढ़ती हैं, थकान हावी होने लगती है और संभावित उत्तराधिकारी अपनी राजनीतिक छुरियां तेज करने लगते हैं। मोदी के तीसरे कार्यकाल का तीसरा वर्ष उत्तराधिकार के अलावा बाकी सभी चुनौतियों से घिरा हुआ है। उनका मंत्रिमंडल संघर्ष कर रहा है। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और हिमंत विश्व शर्मा को छोड़कर उनके मुख्यमंत्री भी कई मोर्चों पर खड़ी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं।

मोदी-भाजपा की कहानी अब भी अहम है लेकिन पहले जैसी प्रभावशाली नहीं है। सार्वजनिक जीवन के 26वें वर्ष में प्रवेश करते हुए मोदी जिस अस्थिरता का सामना कर रहे हैं उसे चौतरफा हवाओं ने और बढ़ा दिया है। इसने मोदी के उस पारंपरिक और अब तक हर चुनावी चुनौती पर भारी पड़ते रहे तीन सूत्री राजनीतिक प्रस्ताव पर 2014 के बाद सबसे अधिक दबाव बना दिया है।

ये तीन बिंदु हैं: कठोर हिंदुत्व-आधारित राष्ट्रवाद, लगातार बढ़ता कल्याणकारी तंत्र, जिसे न्यूनतम बाधाओं और रिसाव के साथ प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाता है और भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण। यह सब बिना किसी खास भ्रष्टाचार के।

परंतु अब कई अन्य कारक भी सामने आ गए हैं। हम केवल उस बेबाक, उम्र पर सवाल को लेकर असहज, शिक्षित और ज्यादातर आर्थिक रूप से वंचित न रहने वाली जेन जी की बगावत की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में इस दौर के संकट को अभूतपूर्व बनाने वाली बात इन सभी कारकों का एक साथ सामने आना है। शेक्सपियर के शब्दों में, 'जब दुख आते हैं तो अकेले जासूसों की तरह नहीं बल्कि पूरी बटालियन के रूप में आते हैं।'

महान प्रबंधन गुरु दिवंगत सी.के. प्रह्लाद कहा करते थे, 'कमजोर संकेत मिलकर बड़े बदलाव का रूप ले लेते हैं।' उन्होंने 1995 में प्रकाशित अपने बहुचर्चित शोधपत्र 'वीक सिग्नल्स वर्सेज स्ट्रॉंग पैराडाइम्स' (सेज जर्नल्स) में इसे विस्तार से समझाया था। प्रह्लाद ने स्वयं इसे इस तरह संक्षेप में बताया था, 'एक-एक करके देखें तो ये संकेत बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। लेकिन जब इन्हें एक साथ देखा जाता है तो ये किसी देश (या उद्योग) में हो रहे नाटकीय बदलाव की तस्वीर पेश करते हैं।'

क्या इस समय मोदी के सामने भी ऐसी ही स्थिति है? आइए, कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की विश्वसनीयता को गंभीर नुकसान पहुंचा है और इसके चलते चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लेकर संदेह बढ़ रहा है।

यह धारणा मजबूत हो रही है कि शीर्ष न्यायपालिका या तो कार्यपालिका के सामने खड़े होने का साहस नहीं करती या फिर ऐसे ढुलमुल आदेश देती है जिनका कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं होता। इससे भी गंभीर बात यह है कि उस पर दोहरे रवैये का आरोप लग रहा है। यह धारणा दोनों पक्षों में साझा है। एक अकेले सेवानिवृत्त अफसरशाह सुभाष चंद्र गर्ग ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर देशव्यापी बहस छेड़ दी है।

आरबीआई के मौजूदा पूर्वानुमान के अनुसार मुद्रास्फीति करीब तीन वर्षों के उच्चतम स्तर तक पहुंचने वाली है और बेहद सफल, हालांकि महंगी, डॉलर-जमा योजना के बावजूद रुपया जूझ रहा है।

इस व्यवस्था के दो सबसे भरोसेमंद अफसरशाहों, दोनों निर्वाचन आयुक्तों (ईसी) ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के फैसलों के प्रति अपनी असहमति को दर्ज करने के लिए दस्तावेजी रिकॉर्ड तैयार करके अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली।

विपक्ष खासकर राहुल गांधी की राजधानी को घेरने की क्षमता बढ़ी है। इसमें अंग्रेजी टीवी चैनलों और हिंदी अखबारों ने, जिनमें सत्ता के 'सबसे भरोसेमंद' माने जाने वाले माध्यम भी शामिल हैं, उन्हें प्रमुख प्रसारण समय और कवरेज दी है।

युवा प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं जबकि उनके दक्षिणपंथी समर्थकों की ओर से इसका कमजोर प्रतिरोध देखने को मिल रहा है। वहीं सीजेपी जैसा रातोरात उभरा मंच एजेंडा तय कर रहा है, चाहे वह नीट का मुद्दा हो या सरकारी स्कूलों की स्थिति।

चिराग पासवान जैसे छोटे सहयोगी ने बिहार सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। इससे भी छोटे सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश को कई राज्यों में बांटने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के साथ अपनी कथित बातचीत को सार्वजनिक कर दिया है। इस प्रस्ताव का योगी आदित्यनाथ दृढ़ता से विरोध करते हैं।

मोदी सरकार की निर्णायक छवि के विपरीत फैसले लेने में लंबे समय से चली आ रही अनिर्णय की स्थिति दिखाई दे रही है। चाहे परिसीमन को आगे बढ़ाने का सवाल हो या फिर संसद सत्र का जिसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के दो महीने बाद भी औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया है। इससे संकेत मिलता है कि भाजपा जो संवैधानिक संशोधन चाहती है उन्हें पारित कराने के लिए जरूरी संख्या जुटाने को लेकर उसमें आत्मविश्वास की कमी है।

इसमें एक और बात जोड़ी जा सकती है मंत्रिमंडल में फेरबदल करने या कम से कम खाली पदों को भरने में लंबे समय से जारी हिचकिचाहट। ऐसे खाली पदों की संख्या बहुत अधिक है जिनमें शिक्षा मंत्रालय भी शामिल है।

मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान शेयर बाजार में लगातार गिरावट आई है जबकि अमेरिका और यूरोप से लेकर जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और यहां तक कि पाकिस्तान तक लगभग सभी वैश्विक समकक्ष बाजारों में तेजी आई है। इस जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता है खासकर तब जब मध्यवर्ग के लाखों लोगों ने अपनी बचत को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) में स्थानांतरित किया है और सरकार भी ऐसा करने के लिए उनकी सराहना करती रही है।

भारत के सामने दशकों में पहली बार ऐसी वैश्विक परिस्थिति है। डॉनल्ड ट्रंप ने कई क्षेत्रों में भारत के रणनीतिक विकल्पों की गुंजाइश सीमित कर दी है। वह लगातार उकसावे के जरिये हमारी रणनीतिक स्वायत्तता के दावों को भी चुनौती दे रहे हैं। ट्रंप से आगे देखें तो यूक्रेन का युद्ध, सुलगता हुआ पश्चिम एशिया, उथल-पुथल से गुजरते ऊर्जा बाजार और पाकिस्तान के लिए रणनीतिक लाभ अर्जित करने का हाल में खुला अवसर भी भारत के सामने मौजूद हैं।

इसके अलावा मॉनसून भी कमजोर रहा है। यह ऐसी स्थिति है जो किसी भी सरकार के नियंत्रण से बाहर है। हालांकि बड़े मुद्दों की जड़ें उन तीन सबसे बुनियादी कारकों में हैं जिन्होंने दशकों से भारत को एकजुट और मजबूत बनाए रखा है। ये कारक हैं संविधान में विश्वास और यह भरोसा कि कोई इसे छीन नहीं सकता, शीर्ष न्यायपालिका की निष्पक्षता और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता। अब तीनों पर दबाव है।

भाजपा अपने विरोधियों से बेहतर जानती है कि 2024 में उसे उन अफवाहों से कितना नुकसान हुआ था जिन्हें उसके कुछ मध्यम स्तर के पदाधिकारियों और अयोध्या के उम्मीदवार के एक-दो बयानों से हवा मिली थी। इनमें कहा गया था कि संविधान बदलने के लिए पार्टी को 400 सीटों की जरूरत है। अधिकांश भारतीयों ने संविधान पढ़ा नहीं लेकिन वे संविधान को किसी देवी-देवता या धर्मग्रंथ की तरह देखते हैं। एक ऐसा निष्पक्ष और धर्मनिरपेक्ष अधिकार-पत्र, जिसे वे किसी को छीनने नहीं देंगे। संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने की लगातार चर्चाओं ने इन आशंकाओं को फिर जगा दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसलों से बार-बार पलटने, टालमटोल करने और लिखने से ज्यादा बोलने की छवि बना ली है। एसआईआर के मुद्दे पर उसका रवैया भी इसी दायरे में आता है। उसकी भूमिका पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो करीब आठ दशकों के दौरान इस संस्था ने अच्छे दिन भी देखे हैं, बुरे दिन भी और कुछ ऐसे दौर भी जब उसका प्रदर्शन न अच्छा था न बुरा। लेकिन आज जैसी स्थिति में वह कभी नहीं रहा। यह एक राष्ट्रीय संकट है।

ये वे चुनौतियां हैं जिनका समाधान मोदी को सार्वजनिक जीवन में लगातार अपने 26वें वर्ष में प्रवेश करते समय करना है। अगर वह ऐसा नहीं करते या ऐसा करने में विफल रहते हैं तो 2029 की गर्मियों तक संकट गंभीर हो सकता है।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय



18- जैन दर्शन

गतांक से आगे...

[1] उमास्वाति रचित - तत्त्वार्थाधिगमसूत्र [प्रथम शताब्दी]

[2] सिद्धसेन दिवाकर रचित - न्यायावतार [533 ई0]

[3] प्रभासचन्द्र रचित -प्रमेयकमलमात्त ण्ड [825 ई0]

[4] हेमचन्द्र रचित- प्रमाणमीमांसा [12वीं सदी]

[5] मल्लिषेण रचित - स्याद्वादमञ्जरी [13 वीं सदी]

19- थेरावाद या प्रारम्भिक पाली बौद्धधर्म

साधारणतया यह स्वीकार किया जाता है कि बौद्धधर्म का सब से प्राचीन रूप-पाली भाषा में विद्यमान त्रिपिटक, में पाया जाता है। बुद्ध ने अपने धर्म या सिद्धान्तों के विषय में कोई ग्रन्थ नहीं लिखा। बौद्ध जन-श्रुति के अनुसार बुद्ध के निर्वाण के कुछ दिन बाद हीं राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति (कौंसिल) हुयी, जिसमें बुद्धके उपदेशों का संग्रह किया गया। निर्वाण के लगभग 110 वर्ष बाद वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुयी, और निर्वाण के 236 वर्ष बाद अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुयी, जिनमें पालो त्रिपिटक का स्वरूप निश्चित किया गया, परन्तु उसकी परम्परा मौखिक हो रही। त्रिपिटक का वत्त मान लेखबद्ध स्वरूप ईसा के पूर्व प्रथम सदी में लङ्का के राजा वट्टगा-मणि अभय के समय में हुआ। पाली त्रिपिटक को मानने वाले ही थेराबादी कहलाते हैं। पाली शब्द बेरा का संस्कन रूप स्थविर है जिसरा अर्थ है वृद्ध या आदरणीय इस प्रकार प्राचीन बौद्ध परम्परा को मानने वाले भिक्षु स्थविर या थेरा कहलाते थे। त्रिपिटक तीन प्रकार के ग्रन्थ समूहों का नाम है, पिटक- पिटारा। 1 सुत्तपिटक 2 विनयपिटक 3 अभिधम्मपिटक।

क्रमशः ...

मिसाइलमैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

सपने वे नहीं होते, जो आपको रात में सोते समय नींद में आए बल्कि सपने वे होते हैं, जो रात में सोने ही न दें। ऐसी बुलंद सोच रखने वाले मिसाइलमैन अवुल पकिर जैनुलाअबदीन अब्दुल कलाम (एपीजे अब्दुल कलाम) भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं। जब कलाम ने देश के सर्वोच्च पद यानी 11वें राष्ट्रपति की शपथ ली थी तो देश के हर वैज्ञानिक का सर फख्र से ऊंचा हो गया था। वे मिसाइलमैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय हुए।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्हें दुनिया मिसाइलमैन के नाम से भी जानती है, का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम् (तमिलनाडु) में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाअबदीन अब्दुल कलाम था। कलाम अपने परिवार में काफी लाड़ले थे, लेकिन उनका परिवार छोटी-बड़ी मुश्किलों से हमेशा ही जूझता रहता था। उन्हें बचपन में ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था।



कलाम जब मात्र 19 वर्ष के थे, तब द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका को भी उन्होंने महसूस किया। युद्ध की आग रामेश्वरम् के द्वार तक पहुंच गई थी। इन परिस्थितियों में भोजन सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया था। कलाम एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आए, तो इसके पीछे उनके 5वीं कक्षा के अध्यापक सुब्रह्मण्यम अय्यर की प्रेरणा जरूर थी।

अध्यापक की बातों ने उन्हें जीवन के लिए एक मंजिल और उद्देश्य भी प्रदान किया। अभियांत्रिकी की शिक्षा के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। वहां इन्होंने एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अध्ययन किया।

1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए। डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह (एसएलवी तृतीय) प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल है। अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं।

उन्होंने 20 साल तक भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन यानी इसरो में काम किया और करीब इतने ही साल तक रक्षा शोध और विकास संगठन यानी डीआरडीओ में भी। वे 10 साल तक डीआरडीओ के अध्यक्ष रहे। साथ ही उन्होंने रक्षामंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की भूमिका भी निभाई। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइल्स को स्वदेशी तकनीक से बनाया था।

18 जुलाई 2002 को कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था जिसका वामदलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया था। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 25 जुलाई 2007 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था।

ऐसे भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के जनक और जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को शिलांग के आईआईएम में एक व्याख्यान देने के दौरान गिरने के बाद निधन हो गया।

ज्ञानेश के खिलाफ विपक्ष के राजनीतिक तांडव की परिणति क्या होगी?

अजय बोकिल

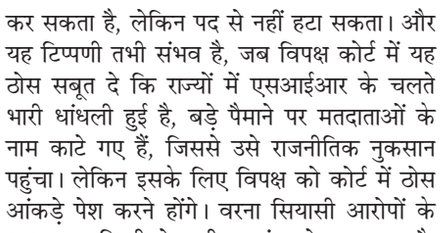
देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहले सीजेपी और एक दिन के अंतराल से कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन, हंगामे और इसके जरिए मोदी सरकार पर बनाए जा रहे दबाव के नरेटिव से सवाल उठ रहा है कि इसका राजनीतिक उद्देश्य क्या है?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और इस आंदोलन के नेता राहुल गांधी ने इसे आंदोलन को 'शिव का तांडव' कहा है। यानी यह प्रत्यक्ष रूप से विपक्ष और परोक्ष रूप से जनता का राजनीतिक तांडव है, जिसकी अंतिम परिणति क्या होगी, अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि शिव का तांडव तो असाधारण क्रोध से उपजता है और इसकी परिणति नए सृजन के रूप में होती है। क्या भारतीय राजनीति में भी वैसा ही कुछ होने जा रहा है? या फिर कुछ दिनो बाद वैसी ही गाजर की सियासी पुंगी बजने लगेगी?

बहरहाल मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) विपक्ष ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा लेने पर अड़ा हुआ है, जबकि भाजपा उनका लगातार बचाव करने में लगी है। विपक्ष सड़कों पर यह कहकर हमलावर है कि भाजपा संविधान को खत्म कर रही है तो भाजपा पत्रकारवार्ताएं करके जवाब दे रही है कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रहा है। हालांकि यह सभी को पता है कि ज्ञानेश जिस संवैधानिक पद पर जमे हैं, उस पर से उन्हें कोई नहीं हटा सकता। सरकार भी नहीं।

ज्ञानेश को केवल संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए जरूरी बहुमत न तो सत्तारूढ़ एनडीए के पास है और न ही विपक्ष के पास। अलबत्ता ज्ञानेश कुमार खुद विपक्ष की घेराबंदी से तंग आकर, आत्मग्लानि में अथवा अंतरात्मा की आवाज पर इस्तीफा दे दें तो बात अलग है। लेकिन ऐसे लोग अलग मिट्टी के बने होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट भी केवल ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और मंशा को लेकर कोई तल्ख टिप्पणी



कर सकता है, लेकिन पद से नहीं हटा सकता। और यह टिप्पणी तभी संभव है, जब विपक्ष कोर्ट में यह ठोस सबूत दे कि राज्यों में एसआईआर के चलते भारी धांधली हुई है, बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जिससे उसे राजनीतिक नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके लिए विपक्ष को कोर्ट में ठोस आंकड़े पेश करने होंगे। वरना सियासी आरोपों के आधार पर किसी से इस्तीफा मांगा तो जा सकता है, लिया अथवा दिलवाया नहीं जा सकता।

वैसे भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल और लंबी है। संविधान ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह ही सुरक्षा दी हुई है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इसके भी केवल दो आधार हैं।

पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा कोई दुर्व्यवहार साबित हुआ हो या फिर वो अपने कर्तव्य निर्वहन में अक्षम सिद्ध हुए हों। महाभियोग की प्रक्रिया काफी लंबी है। मसलन सबसे पहले महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर स्वीकृति देने, न देने का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्षों के पास होता है।

स्वीकृति भी प्रस्ताव की जांच की बाद दी जा सकती है। अध्यक्ष पहले जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करते हैं। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होता है। समिति सम्बन्धित व्यक्ति पर लगाए आरोपों की जांच कर तय करती है कि आरोपी द्वारा दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हुई है या नहीं। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर दोनो सदनों में महाभियोग प्रस्ताव मतदान द्वारा विशेष बहुमत से पारित करना होता है।

विशेष बहुमत बोले तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत या मतदान के दिन सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से दो तिहाई । संसद की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का आदेश जारी करते हैं। सदन की वर्तमान संरचना में महाभियोग प्रस्ताव पारित कराना टेढ़ीखीर है। और फिर मोदी सरकार ऐसा क्यों होने देगी, खासकर तब कि जब विपक्ष दूसरे तमाम मुददों को हाशिए पर डालकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर ही पिल पड़ा हो।

लिहाजा पूरे मामले का अहम पक्ष है इसका राजनीतिक उद्देश्य। यह जानते हुए भी कि ज्ञानेश कुमार पद से इतनी आसानी से नहीं हटाए जा सकेंगे, विपक्ष का मकसद यह नरेटिव सेट करना है कि मोदी सरकार अब आरोपों में बहुत गहरे तक घिर गई है। वह धांधली कराकर चुनाव जीतती जा रही है। उसे जनता की आवाज की कोई चिंता नहीं है। इस सरकार को अब जाना चाहिए। हालांकि वो हटी तो कौन आ सकता है, यह भी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी इसका विकल्प नहीं बताते।

उनका मानना शायद यह है कि हालात इतने खराब हैं कि जनता बिना यह सोचे कि मोदी की जगह किसको जिताएं, यह सोचकर वोट देगी कि पहले इसे हटाएं बाकी बाद में देखेंगे। या यूं कहें कि अब जनता ही सत्ता परिवर्तन का तांडव करेगी तो नई राजनीतिक कोंपले खुद ब खुद फूटने लगेंगी।

असमाप्त लगने वाला यह आंदोलन एक नरेटिव सेट करने में तो कुछ हद तक सफल होता दिख रहा है, वो ये कि देश में सब ठीक नहीं है। युवाओं का बेखौफ सड़कों पर उतरना, दिल्ली में बार-बार हो रहे धरना-प्रदर्शन इसी व्यापक असंतोष का नतीजा हैं, जो कभी पेपर लीक, कभी नौकरी की प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी तो कभी वोट चोरी के रूप में प्रकट होता है।

दिल्ली के प्रदर्शनों के रील पूरी दुनिया में वायरल हुए। इनमें भी दोतरफा एजेंडा सेट करने की कोशिशें दिखीं। पहला तो यह कि भारत में मोदी-शाह के तानाशाही रवैये के चलते हालात बहुत खराब हो चुके हैं और जनता बगावत पर उतर आई है। महिलाओं, पत्रकारों को भी पीटा जा रहा है। सरकार दमन का सहारा ले रही है। राष्ट्रवादियों ने देश को बर्बाद कर दिया है। ऐसे में विपक्ष और कॉकरोच किसी कीमत पर नहीं झुकेंगे।

दूसरा एजेंडा यह था कि दिल्ली की सड़कों पर जो रहा है, वह मोदी विरोधी टूलकिट का ही एक और प्रयोग है, जिसका पहला और अंतिम उददेश्य केवल देश में अस्थिरता पैदा करना है। वैसे इस पूरे इस आंदोलन का पब्लिक कनेक्ट कितना है, यह तो किसी बड़े चुनाव में ही पता चलेगा।

इसी संदर्भ में एक अमेरिकी पत्रकार असरा नोमानी की यह चेतावनी अहम है कि भारत में इस्लामी और वामपंथी ताकतें वैसे ही हालात पैदा करना चाहती हैं, जैसी कि उसने नेपाल और बांगलादेश और अब यूरोप में कर रही हैं। हालांकि इस आंदोलन की एक दिलचस्प बात यह भी है कि एक ही मांग को लेकर दो अलग-अलग आंदोलन हो रहे हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन और सीजेपी के पांव अलग-अलग चल रहे हैं। जबकि शिव के तांडव में कोई शेयरिंग नहीं होती। भगवान शिव स्वयं ही काफी हैं।

फिर वही सवाल कि इस तांडव का उद्देश्य क्या है? राहुल गांधी का कहा है कि हमारा अंतिम लक्ष्य ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेना भर नहीं है बल्कि उन्हें बचाने वालों को सत्ता से बेदखल करना है। यानी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सत्ता से हटाना है। लेकिन वो इसका रोड मैप साफ नहीं करते।

आज का इतिहास

1894 अलफ्रेड ड्राइफ़स पर पेरिस में मुक़द्दमा आरंभ हुआ था।
1917 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड की प्रसिद्ध नृत्यांगना माता हारी को जर्मनी के लिए जासूसी करने के आरोप में फ्रांसीसी सैनिकों ने गोली मारी थी।
1923 पांचवां उष्णकटिबंधीय तूफान लीवर्ड द्वीप के उत्तर में आया था।
1924 अमेरिकी राष्ट्रपति काल्विन ने स्टेच्यु ऑफ लिबर्टी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया।
1932 टाटा कंपनी के हवाई जहाज ने अपनी पहली उड़ान भरी। जिसके बाद भारत सरकार ने कंपनी का अधिग्रहण करके एयर इंडिया नाम रख दिया था।
1949 त्रिपुरा राज्य को भारत में सम्मिलित किया गया था।
1951 मिस्त्र की संसद ने स्वेज नहर समझौते को रद्द करने के फैसले पर मुहर लगाई थी।
1958 अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया ने मिस्त्र के साथ राजनयिक संबंध समाप्त किए थे।
1964 सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्श्चेव की सेवानिवृति ने पूरे विश्व को चौंका दिया था।
1970 अनवर सदत को मिस्त्र का राष्ट्रपति चुना गया था।
1978 सोवियत संघ ने पूर्वी कजाखस्तान क्षेत्र में वर्ष परमाणु परीक्षण किया था।
1988 पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा करने वाली एशिया की प्रथम महिला उज्ज्वला पाटिल बनी।
1990 सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था।
1996 फिजी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि की पुष्टि करने वाला प्रथम देश बना था।
1997 अरुंधति राय को उनके उपन्यास द गॉड आफ़ स्माल थिंग्स के लिए ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था।
1998 ग़रीबी उन्मूलन के लिए भारत की फ़ातिमा बी को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1999 चीन ने 12 हज़ार किलोमीटर तक मार करने वाले डी.एफ़.-41 आईसीबीएम नामक प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया था।
2006 संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाया था।
2007 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के तीन अर्थशास्त्रियों - लियोनिड हरविक्ज, इरिक मस्किन और रोजर मायरसन को प्रदान किया गया था।
2008 भारतीय रिजर्व बैंक ने सीआरआर में एक फ़ीसदी की कटौती की घोषणा की थी।

आंदोलन की गूंज और चुनाव में सत्ता की विदाई

सत्येंद्र प्रताप सिंह

जेपी आंदोलन के बाद 1977 में इंदिरा गांधी और अन्ना आंदोलन के तीन साल बाद 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार चुनाव में सत्ता से बाहर हुई। दिल्ली में 2013 में शीला दीक्षित के 15 साल के शासन का अंत भी चुनावी फैसले से हुआ। रामलीला मैदान से उठी आवाजों ने राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया, लेकिन क्या आंदोलनों ने इन सरकारों की विदाई की जमीन तैयार की?

ऐतिहासिक जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शनों और धरनों के अधिकृत स्थलों की सूची से हटाए जाने के बाद अब रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी ग्राउंड को नए ठिकानों के रूप में निर्धारित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर हुए इस बदलाव के बीच रामलीला मैदान का इतिहास खास मायने रखता है।

दिल्ली का रामलीला मैदान केवल राजनीतिक रैलियों का स्थल नहीं रहा। यह उस जन-असंतोष का प्रतीक भी बना, जिसने सत्ता के सामने सवाल खड़े किए। यहां जुटी भीड़ ने कई बार देश का ध्यान उन मुद्दों की ओर खींचा, जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। यह महज धरना-प्रदर्शन की जमीन नहीं, बल्कि वह मंच है जहां से उठी आवाजों ने सत्ता को चुनौती दी, राजनीतिक विमर्श बदला और कई बार चुनावी राजनीति की दिशा को प्रभावित किया।

आंदोलन में उमड़ी भीड़ और चुनाव में मिलने वाले जनादेश को लेकिन एक मान लेना सही नहीं होगा। लोकतंत्र में सरकार का भविष्य चुनाव और विधायी बहुमत तय करते हैं। आंदोलन की भूमिका इससे पहले शुरू होती है। वह किसी मुद्दे को राष्ट्रीय बहस में ला सकता है, सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकता है और जनता के सामने नए राजनीतिक विकल्पों की मांग को मजबूत कर सकता है। इसी कसौटी पर जेपी आंदोलन, अन्ना आंदोलन और शीला दीक्षित की सत्ता से विदाई को समझना जरूरी है।

जेपी आंदोलन: आपातकाल और हार- 1970 के दशक में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बढ़ते असंतोष ने देश की राजनीति को प्रभावित किया। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के नेतृत्व में आंदोलन ने व्यापक रूप लिया। बिहार से शुरू हुई यह लहर केंद्र की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी की विशाल रैली हुई। इसी दिन उन्होंने सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। इसके अगले दिन देश में आपातकाल लागू होने की घोषणा हुई। नागरिक स्वतंत्रताओं पर पाबंदियां लगीं, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया और प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए। आपातकाल के बाद मार्च 1977 में लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस को करारी हार मिली और इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। यह लोकतांत्रिक अधिकारों और आपातकाल के अनुभव पर जनता के फैसले के रूप में भी देखा गया।

हालांकि, इंदिरा गांधी की सत्ता का अंत केवल रामलीला मैदान की रैली का परिणाम नहीं था। जेपी आंदोलन, आपातकाल के खिलाफ असंतोष और चुनावी परिस्थितियों ने मिलकर राजनीतिक बदलाव की जमीन तैयार की। आंदोलन ने चुनौती खड़ी की, लेकिन सत्ता से विदाई का फैसला मतदाताओं ने किया।

अन्ना आंदोलन: भ्रष्टाचार बना राष्ट्रीय मुद्दा- वर्ष



2011 में रामलीला मैदान एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आया। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल कानून की मांग को लेकर आंदोलन किया। उनके अनशन को युवाओं, शहरी मध्यम वर्ग और समाज के विभिन्न तबकों से समर्थन मिला। मीडिया ने भी इसे देशव्यापी पहचान दी। उस समय मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों और शासन की विश्वसनीयता को लेकर सवालों का सामना कर रही थी। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन और राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े विवादों ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया था। अन्ना आंदोलन ने इन सवालों को व्यापक जनचर्चा का हिस्सा बना दिया।

लेकिन क्या इस आंदोलन ने मनमोहन सिंह की सरकार गिरा दी? तथ्य यह है कि यूपीए सरकार ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने केंद्र में सरकार बनाई।

इसलिए अन्ना आंदोलन को सरकार की सीधी विदाई का कारण बताना सही नहीं होगा। फिर भी, भ्रष्टाचार के मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाने और कांग्रेस विरोधी माहौल को मजबूत करने में इसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

शीला दीक्षित: अन्ना आंदोलन और बदली दिल्ली- दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1998 से लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीते थे। उनके 15 साल के शासन में मेट्रो और शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ, लेकिन तीसरे कार्यकाल के अंतिम दौर में महंगाई, बिजली-पानी की कीमतों और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर असंतोष बढ़ रहा था। अन्ना आंदोलन से जुड़े अरविंद केजरीवाल ने बाद में आम आदमी पार्टी बनाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में उठे सवालों को उन्होंने चुनावी राजनीति का आधार बनाया। इस तरह विरोध की आवाज एक नए राजनीतिक विकल्प में बदल गई।

दिसंबर 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा 31 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी ने अपने पहले ही चुनाव में 28 सीटें जीत लीं, जबकि कांग्रेस आठ सीटों पर सिमट गई। नई दिल्ली सीट से खुद शीला दीक्षित अरविंद केजरीवाल से हार गईं। 28 दिसंबर 2013 को केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यहां भी अंतर समझना जरूरी है। शीला दीक्षित की सरकार को रामलीला मैदान के किसी एक प्रदर्शन ने नहीं हटाया। दिल्ली की स्थानीय समस्याओं, कांग्रेस के खिलाफ असंतोष और आम आदमी पार्टी के उभार ने मिलकर चुनावी नतीजों को प्रभावित किया। अन्ना आंदोलन ने नई राजनीतिक ऊर्जा पैदा की, लेकिन उसका चुनावी परिणाम कई कारकों से तय हुआ।

तीन घटनाएं, एक सवाल- इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित की सरकारों के अंत में एक समानता जरूर है—राजनीतिक बदलाव का अंतिम फैसला चुनाव ने किया। लेकिन तीनों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं थीं। इंदिरा गांधी की हार आपातकाल के बाद हुई; मनमोहन सिंह की सरकार ने कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनाव गंवाया; शीला दीक्षित की सत्ता दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाप्त हुई।

इन घटनाओं से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि रामलीला मैदान पर प्रदर्शन होते ही किसी सरकार की विदाई तय हो जाती है। आंदोलन का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसका मुद्दा कितना व्यापक है, जनता उससे कितना जुड़ती है और विपक्ष या कोई नया राजनीतिक विकल्प उस असंतोष को चुनावी समर्थन में कितना बदल पाता है।

लोकतंत्र में आंदोलन और चुनाव राजनीतिक प्रक्रिया के दो अलग पहलू हैं। आंदोलन सत्ता से सवाल पूछता है; चुनाव जनता को उन सवालों के आधार पर फैसला सुनाने का अवसर देता है।

रामलीला मैदान की ऐतिहासिक भूमिका इसी में है। जेपी आंदोलन ने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रश्न उठाया, अन्ना आंदोलन ने भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में रखा और उससे निकली राजनीतिक ताकत ने दिल्ली में नया विकल्प प्रस्तुत किया।

रामलीला मैदान सरकारों की विदाई का संवैधानिक रास्ता नहीं, लेकिन सत्ता को चुनौती देने वाली आवाजों का महत्वपूर्ण मंच जरूर है। आंदोलन राजनीतिक जमीन तैयार कर सकता है; उस जमीन पर सत्ता किसकी बनेगी, इसका फैसला जनता अपने वोट से करती है।

आपको कौन चाहिए देशभक्त या देशद्रोही

एस.पी. मलिक



भगवान से बड़ा समूचे ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं है। लेकिन आज का समाज/संसार अपने को ही बड़ा सिद्ध करने में जुटा है, किस आधार पर-विज्ञान के आधार पर। परन्तु वह यह भूल जाता है कि तेरी जिसने यह खोपड़ी बनाई, वह भगवान ही तो है यानी अपने निर्माता-परमपिता को ही तुच्छ बना दिया। ठीक वही नमूना हमारे समाज, परिवारों में हम देख रहे हैं। कोई किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार ही नहीं। सब अपनी मनमर्जी की अर्जी लगा रहे हैं। यानी न कोई बड़ा न छोटा, न धर्म न कर्म, न देशभक्ति न समाज का डर। कब तक चलेगा यह ड्रामा। जिसको देखो देश-विरोध में उतर गया है, राजनीति के नाम पर आखिर यह कब तक स्वीकार्य होगा? नहीं होगा...।

फिर समाधान क्या है? एकमात्र समाधान है कि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही शक्तियां सक्रिय हैं, उनके फन को निर्ममता से कुचल दिया जाए, तभी देश बचेगा, तभी सनातन बचेगा। जो संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं, उन्होंने ही इसको कुचला है। ऐसे देशद्रोहियों को यह समाज व देशवासी क्यों जवाब नहीं दे रहे, समझ में नहीं आता। लोगों ने देश में उनका लम्बा शासन-प्रशासन देखा है, फिर भी उनकी बातों में क्यों फंस रहे हैं? जवाब एक ही है-सब अपने निजी स्वार्थों में फंसे हैं। देश की इक्षचता उनको लेशमात्र भी नहीं है। भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, कमीशन तथा हकदारों का हक खा जाना यही उनकी फितरत रही है।

उपाय क्या है इसका? है, बिल्कुल स्पष्ट है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार वोट का अधिकार जनता के पास है। परन्तु कुछ वर्ग-जाति, संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण ऐन वक्त पर गलत प्रचार के कारण लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसी का फायदा ये देश विरोधी भ्रष्टतंत्र के लोग उठाते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम है। देश का सौभाग्य है कि परमात्मा की कृपा से इस देश को निस्स्वार्थ, निर्भय, निडर, मेहनती, निष्ठावान, ग्लोबल नेता एवं देश के प्रति पूर्ण समर्पित प्रधानमंत्री के रूप में मिला है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। भूतो न भविष्यति॥ यानी ऐसा सौभाग्य परमात्मा कभी-कभी प्रदान करते हैं। न किसी की सुनें न मानें।

पिछले 12 वर्षों में भारत के विकास मॉडल का विश्लेषण करें तथा साथ में पिछले 60-70 वर्षों के विकास, भ्रष्टाचार, कमीशनखोर सरकारों का काम देखें, उनके किस्से सुनें-पढ़ें, आपकी आंखें एवं दिमाग आपको स्पष्ट गवाही दे देगा। जितने भी देखे-परखे तिलचट्टे शोर मचा रहे हैं, उनको यह देश देख-परख चुका है। आज की पीढ़ी के कुछ गुमराह तत्व इसके झांसे में आ रहे हैं, उनको भी भारत का देशभक्त समाज जवाब दे देगा, चिंता मत करें। संक्षेप में ऐसा भारत न कभी था (इस लोकतंत्र में), न कभी वर्तमान नेतृत्व के बिना हो सकता है। विश्लेषण के बाद फैसला आपने करना है कि आपको देशभक्त चाहिएं या देशद्रोही।

भाजपा के सामने एक राजनीतिक पहेली!

हरीश गुप्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जल्द ही एक राजनीतिक पहेली खड़ी हो सकती है। उनके मंत्रिमंडल में कम से कम तीन अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, ईसाई और सिख का प्रतिनिधित्व नहीं रह जाएगा। मुस्लिम प्रतिनिधित्व काफी पहले ही समाप्त हो गया था, जब मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया और मीटू विवाद के बीच एम.जे। अकबर को इस्तीफा देना पड़ा।

एक अन्य लोकप्रिय मुस्लिम नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को भी मोदी ने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। वे 2014 के लोकसभा चुनाव में हार गए थे और बाद में राज्य की राजनीति में चले गए। ईसाई प्रतिनिधित्व भी तब समाप्त हो गया, जब इसी साल अप्रैल में केंद्रीय मंत्री के रूप में राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ा और उन्हें पद छोड़ना पड़ा।

केजे अल्फोंस को पर्यटन मंत्री के पद से हटाए जाने के बाद जॉर्ज कुरियन मोदी सरकार में एकमात्र ईसाई मंत्री थे। मोदी सरकार में सिख प्रतिनिधित्व का मुद्दा इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। हालांकि हरदीप सिंह पुरी मोदी सरकार में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उन्हें राज्यसभा का कार्यकाल विस्तार नहीं मिला है। और उनका कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। तकनीकी रूप से पुरी राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी छह महीने तक मंत्री बने रह सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे कम से कम पंजाब विधानसभा चुनाव तक पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन उनके राजनीतिक



भविष्य को लेकर अनिश्चितता की तलवार लटक रही है।

आरएसएस ने पंजाब में राजनीति का रुख बदला- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पंजाब में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। अपनी पारंपरिक शाखा व्यवस्था पर मुख्य रूप से निर्भर रहने के बजाय, संघ चुपचाप समाज में अपनी पहुंच का विस्तार कर रहा है। इसके लिए उसने एक ऐसे माध्यम को चुना है, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो - खेल। रणनीति सरल है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

अधिक शाखाएं खोलने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, आरएसएस खेल क्लबों के गठन को प्रोत्साहित कर रहा है, स्थानीय टूर्नामेंट और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवा रहा है तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को अपने जनसंपर्क कार्यक्रम का हिस्सा बना रहा है। इसका उद्देश्य पंजाब के लोगों के जुनून यानी खेल के माध्यम से समुदायों के बीच अपनी जगह बनाना और जमीनी स्तर पर संबंध विकसित करना है।

राजनीतिक दृष्टि से इसके पीछे विचार है- पहले सामाजिक नेटवर्क बनाएं, फिर राजनीति को अपनाएं। इस रणनीति का समय भी महत्वपूर्ण है। जालंधर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को पंजाब की एक 'नई अर्थव्यवस्था' बताया। उन्होंने राज्य के खेल विश्वविद्यालयों, खेल सामग्री निर्माण केंद्र और यहां से निकले अनगिनत चैंपियनों का जिक्र किया।

लेकिन ऐसा लगता है कि आरएसएस खेलों को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाए जाने से काफी पहले ही इस दिशा में काम शुरू कर चुका था। भाजपा के लिए पंजाब में स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक पकड़ बनाना कभी आसान नहीं रहा है। शिरोमणि अकाली दल के साथ दशकों पुराने गठबंधन के कारण भाजपा की भूमिका मुख्यत: छोटे सहयोगी दल की रही। उसका संगठनात्मक प्रभाव भी पारंपरिक शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। अब यह समीकरण बदल रहा है। भाजपा को उस चीज की जरूरत है, जिसकी उसके पास ऐतिहासिक रूप से कमी रही है - एक व्यापक और स्वतंत्र जमीनी संगठनात्मक नेटवर्क। यहीं आरएसएस का पंजाब में यह नया प्रयोग भाजपा के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

खेल प्रतियोगिताएं, खेल क्लब और सांस्कृतिक कार्यक्रम भले ही राजनीतिक गतिविधियां न दिखें, लेकिन इनके पीछे राजनीतिक संभावनाएं मौजूद हैं। भाजपा शायद सीटों का हिसाब लगा रही है, जबकि आरएसएस लोगों के साथ अपने संबंधों का नेटवर्क तैयार कर रहा है।

राहुल गांधी भी चले अपने चाचा की राह!- राहुल गांधी ने राजनीति में एक नया हथियार खोज लिया है - सड़क पर उतरकर संघर्ष करना। अब पुराने ढर्रे के पूर्वानुमानित प्रदर्शनों को भूल जाइए। वे चाहते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता तत्काल परिस्थितियों के अनुसार कदम उठाएं, सड़कों पर उतरकर मुकाबला करें और ऐसे दृश्य पैदा करें जो सोशल मीडिया पर राजनीतिक भाषणों से कहीं अधिक तेजी से फैलें। इस उभरती रणनीति में अचानक निकाले जाने वाले मार्च, बिना पूर्व योजना के धरने, बैरिकेड पार करना और पुलिस के साथ जोरदार टकराव शामिल हैं। इसका उद्देश्य स्पष्ट है - दृश्य प्रभाव पैदा करना, समाचार चक्र पर नियंत्रण हासिल करना और प्रशासन को अचानक चुनौती देना।

रील्स और जेन-जी की राजनीति के इस दौर में 30 सेकंड का एक नाटकीय वीडियो कभी-कभी तीन घंटे की रैली से भी अधिक ध्यान आकर्षित कर सकता है। हाल के विरोध प्रदर्शनों में इस रणनीति की झलक देखने को मिली है। इनमें वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का शर्टलेस प्रदर्शन और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों के मार्च तथा धरने शामिल हैं। जब पुलिस एक रास्ता रोकती है तो अचानक किसी दूसरे स्थान पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकता है।

राहुल गांधी की जमीनी स्तर पर सक्रियता ने गति पकड़ ली है। नीट प्रश्नपत्र लीक विवाद को लेकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर उनका धरना और उसके बाद दिल्ली में अक्टूबर के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों में टकराव ने यह संदेश मजबूत किया है कि कांग्रेस को केवल बयान जारी करने के बजाय संघर्ष करते हुए दिखाई देना चाहिए।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि राहुल ने केसी वेणुगोपाल से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सांसद सड़क पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों में शामिल हों। अनुपस्थित रहने वाले सांसदों से जवाब भी मांगा जा रहा है। शायद वे दिवंगत संजय गांधी के नक्शेकदम पर चल रहे हैं, जो एक उग्र नेता थे और 1980 में सत्ता में वापसी करने में सफल रहे थे।

जिओ आईपीओ को नुकसान पहुँचाने एलन मस्क ने चला बड़ा दाँव

नीरज कुमार दुबे

स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क का दुस्साहस बढ़ता ही चला जा रहा है। भारतीय उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी पर सोशल मीडिया के जरिये निशाना साधने के बाद अब जियो के प्रस्तावित आईपीओ से ठीक पहले एलन मस्क ने तीखे बयान दिये हैं। जिन्हें भारतीय बाजार में अपनी एंट्री के लिए दबाव बनाने और रिलायंस के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि एलन मस्क ने आरोप लगाया है कि भारत में कुछ प्रभावशाली कारोबारी हित उनकी कंपनी स्टारलिंक का रास्ता रोक रहे हैं। साथ ही, उन्होंने भारत में सस्ती सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने का वादा किया है। हालांकि, सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि जियो और भारती समर्थित वनवेब भी जरूरी मंजूरियों के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मस्क के आरोप तथ्यों पर आधारित हैं या जियो के आईपीओ से पहले प्रतिस्पर्धा को लेकर एकतरफा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है?

उल्लेखनीय है कि मस्क ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर दावा किया कि भारत में कुछ प्रभावशाली कारोबारी हित स्टारलिंक की एंट्री रोककर अपने एकाधिकार को बचाना चाहते हैं। उन्होंने अंबानी पर भी निशाना साधते हुए प्रतिस्पर्धा की अनुमति देने की बात कही। साथ ही वादा किया कि भारत में स्टारलिंक की सेवा सस्ती रखी जाएगी, क्योंकि महंगी सेवा होने पर ग्राहक उसे नहीं अपनाएंगे। मस्क का तर्क है कि प्रतिस्पर्धा से भारतीय उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलेंगे, भले ही इससे अंबानी के मुनाफे पर दबाव पड़े।

लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत में स्टारलिंक की व्यावसायिक शुरुआत में देरी के लिए वास्तव में जियो या अंबानी जिम्मेदार हैं? दूरसंचार विभाग के रिकॉर्ड पर आधारित रिपोर्ट इस दावे की दूसरी तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और भारती समर्थित वनवेब ने स्टारलिंक से पहले अपनी सुरक्षा



और तकनीकी अनुपालन संबंधी प्रक्रियाएं पूरी कर ली थीं। जियो ने 20 मार्च 2025 को अपना सुरक्षा एवं तकनीकी प्रदर्शन पूरा किया, जबकि वनवेब ने 2025 की दूसरी छमाही में यह प्रक्रिया पूरी की। स्टारलिंक का प्रदर्शन 2026 की शुरुआत में हुआ। ऐसे में यह कहना कि केवल भारतीय प्रतिस्पर्धियों के प्रभाव के कारण स्टारलिंक को रोका जा रहा है, यह सरासर गलत है।

देखा जाये तो लाइसेंस और मंजूरी की समयरेखा भी इस बहस को समझने में मदद करती है। वनवेब को अगस्त 2021 में दूरसंचार विभाग से आशय-पत्र मिला और अप्रैल 2022 में उसे जीएमपीसीएस लाइसेंस मिला। जियो ने नवंबर 2021 में लाइसेंस के लिए आवेदन किया और अक्टूबर 2022 में प्राधिकरण हासिल किया। इसके विपरीत, स्टारलिंक को जीएमपीसीएस लाइसेंस 6 जून 2025 को मिला। यानी भारतीय कंपनियां इस प्रक्रिया में पहले से मौजूद थीं, फिर भी उनकी सेवाएं व्यावसायिक रूप से शुरू नहीं हो सकी हैं। तीनों कंपनियों को अंतिम सुरक्षा मंजूरी और स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रतीक्षा है। यदि जियो और वनवेब को बाजार में स्टारलिंक को रोकने के लिए विशेष सुविधा मिल रही होती, तो सवाल उठाए जा सकते थे।

इसके अलावा, सैटेलाइट इंटरनेट का मामला सामान्य दूरसंचार सेवा से अलग है। इसके नेटवर्क की पहुंच सीमाओं से परे हो सकती है, इसलिए नेटवर्क की निगरानी, वैध अवरोधन और भारतीय कानूनों के अनुपालन जैसे विषय महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षा संबंधी शर्तें पूरी होने के बाद ही स्पेक्ट्रम आवंटन और व्यावसायिक परिचालन का रास्ता साफ हो सकता है। हम आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार ने मस्क के भेदभाव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि नियामकीय ढांचा निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण है। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी स्पष्ट किया है कि कंपनियां जरूरी सुरक्षा और नियामकीय शर्तें पूरी करने के बाद ही सेवाएं शुरू कर सकती हैं। देखा जाये तो भारत के लिए इस मामले में प्राथमिकता किसी कारोबारी घराने के हितों की रक्षा करना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार करना होना चाहिए। स्टारलिंक को भी अन्य कंपनियों की तरह समान नियमों का पालन करना होगा। केवल वैश्विक प्रतिष्ठा, तकनीकी क्षमता या बाजार में निवेश की इच्छा के आधार पर सुरक्षा संबंधी शर्तों में छूट नहीं दी जा सकती।

अब सवाल उठता है कि जियो के आईपीओ पर कितना असर पड़ेगा? हम आपको बता दें कि जियो प्लेटफॉर्म्स 106 अरब डॉलर के मूल्यांकन को लक्ष्य बनाकर अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। ऐसे समय में मस्क का अंबानी पर सार्वजनिक हमला और सस्ती स्टारलिंक सेवा का वादा बाजार में चर्चा पैदा कर रहा है। लेकिन निवेशकों के लिए एलन मस्क के बयान की बजाय जियो कंपनी की वित्तीय स्थिति, विकास की संभावनाएं, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और नियामकीय जोखिम जैसे कई कारक महत्वपूर्ण होंगे। इसी तरह, स्टारलिंक की भारतीय बाजार में वास्तविक चुनौती उसकी कीमत, कवरेज, सेवा की गुणवत्ता और आवश्यक मंजूरियां मिलने पर निर्भर करेगी।

बहरहाल, भारत में कारोबार करने की इच्छा रखने वाली किसी भी विदेशी कंपनी का स्वागत प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों के आधार पर होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्तों के साथ। मस्क की बयानबाजी से मंजूरी की प्रक्रिया तेज हो या न हो, उसका फैसला नियमों और तथ्यों के आधार पर ही होना चाहिए।

लोकतंत्र की लड़ाई या राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन

कांतिलाल मांडोत

दिल्ली में 12 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों का प्रदर्शन राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते हुए बाराखंबा से सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला। इसके बाद एसआईआर में कथित अनियमितताओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने की पहल की गई। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनावी प्रक्रिया, संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका और राजनीतिक विरोध की मर्यादा को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। इस मार्च में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राउत, सौगत राय और विभिन्न विपक्षी दलों के अन्य नेता शामिल हुए। समाचार के अनुसार दस विपक्षी दलों के ग्यारह नेताओं ने याचिका में पक्षकार बनने की पहल की। निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी मामले में पक्ष बनाया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुली गाड़ी में नजर आए, जबकि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव सहित दूसरे नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। राहुल गांधी सबसे आगे और उनके आगे प्रियंका गांधी के चलने की बात भी सामने आई। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों तथा अन्य विपक्षी नेताओं की भागीदारी ने इस मार्च को व्यापक राजनीतिक प्रदर्शन का रूप दिया। मार्च से पहले राहुल गांधी ने लगभग चालीस मिनट तक पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने विपक्ष के इस जमावड़े की तुलना भगवान शिव की बारात से करते हुए कहा कि इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियां लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं और इन्हें दूर करना जरूरी है। दूसरी ओर, ऐसे आरोपों की वास्तविकता का निर्धारण राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि दस्तावेजों, प्रमाणों और संबंधित संस्थाओं के उत्तरों के आधार पर होना चाहिए। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की कसौटी है। रविवार को विपक्षी सांसदों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को पत्र लिखकर ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था। उसके अनुसार उन्हें मिलने का समय नहीं मिला और याचिका दाखिल करने का रास्ता अपनाने को कहा गया। इसके बाद विपक्ष ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की दिशा में कदम बढ़ाया। राहुल गांधी की कानूनी टीम ने याचिका दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग भी की। यहां यह समझना जरूरी है कि किसी याचिका का दाखिल होना और उसमें लगाए गए आरोपों का न्यायिक रूप से सही साबित होना दो अलग-अलग बातें हैं। न्यायालय में मामला पहुंचने के बाद तथ्यों और कानून के आधार पर ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों और कानूनी प्रक्रिया से जुड़े लोगों की भागीदारी ने इस विवाद को संवैधानिक बहस का रूप दिया है। न्यायपालिका की भूमिका राजनीतिक पक्षों के नारों के आधार पर फैसला सुनाना नहीं, बल्कि कानून, प्रमाण और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विवाद का समाधान करना है। मुख्य न्यायाधीश ने विपक्षी नेताओं को न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से आने की सलाह दी थी, क्योंकि संबंधित विषय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थे। यह व्यवस्था की संस्थागत मर्यादा का महत्वपूर्ण पहलू है। न्यायालय में याचिका दाखिल होने के बाद सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए और निर्णय का सम्मान करना चाहिए। अंतत: दिल्ली का यह घटनाक्रम केवल एक मार्च या एक दिन के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। यह चुनावी पारदर्शिता, राजनीतिक जवाबदेही, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास और विरोध की सीमाओं से जुड़े व्यापक प्रश्न सामने लाता है।



निखारें चेहरा संवारें अपना भविष्य

पार्टियों में जाने के लिए किए जाने वाले मेकअप से लेकर कलाकारों के मेकअप तक इसकी उपयोगिता से सभी परिचित हैं, लिहाजा यह मेकअप करना शौक भी हो सकता है और एक कामयाब करियर भी। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कुछ वर्ष पहले तक करियर के रूप में इसे अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, लेकिन अब बाजार के बड़े-बड़े नामों ने इसमें सम्मान जोड़ दिया है। कुछ कामयाब नाम हैं- शहनाज हुसैन, भारती तनेजा, वंदना लूथरा, ब्लॉसम कोचर, सिल्वी इत्यादि। इन्होंने मेकअप आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत की और आज बिजनेस ब्रांड के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं। यही वजह है कि अब मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर करियर बनाने के इच्छुक युवा ट्रेनिंग लेने लगे हैं, ब्यूटी चेन में अच्छी जॉब उन्हें मिलने लगी है और कम पूंजी में खुद का व्यवसाय शुरू करने लगे हैं। आज मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ फैशन मॉडल्स अथवा फिल्मी सितारों की ही जरूरत नहीं है। दूसरी जगहों पर भी इसकी खास डिमांड है। खासकर शादी के सीजन में इन लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। अब तो इसमें भी स्पेशलाइजेशन हो गया है, जैसे कोई सिर्फ दूल्हे का मेकअप करता है तो कोई दुल्हन का। यहां आपको यह बता दें कि हर माध्यम के लिए अलग-अलग मेकअप होता है। टीवी/फिल्मी कलाकारों का मेकअप अलग होता है तो थिएटर में काम करने वालों का अलग। स्टेज आर्टिस्ट का मेकअप टीवी आर्टिस्ट की तुलना में चटक होगा। किसी कैरेक्टर को उसकी उम्र से अलग दिखाना है तो उसका मेकअप अलग होगा, वहीं जले या दाग दिखाने के लिए मेकअप अलग होगा। शहर और वहां की जलवायु के मुताबिक भी मेकअप किया जाता है। जैसे मुंबई में हवा में नमी रहती है, इसलिए पसीने को ध्यान में रख कर ऐसा मेकअप करना पड़ता है कि वह खराब न हो। वहीं राजस्थान में मेकअप के लिए अलग चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह तभी संभव है, जब मेकअप आर्टिस्ट को इसका ठीक-ठीक ज्ञान हो कि स्थान, उम्र और जरूरत के लिहाज से कैसा मेकअप होना चाहिए।

मेकअप आर्टिस्ट किसी जवान इंसान को बूढ़ा बना देता है तो बूढ़े इंसान को जवान। यही नहीं, मेकअप में वो ताकत है, जो चरित्र के हिसाब से कलाकार का पूरा व्यक्तित्व बदल दे। सुंदर दिखने-दिखाने की चाहत व्यक्तिगत रुचि से लेकर व्यावसायिक कौशल तक फैली हुई है। यही कारण है कि मेकअप करना एक खास किस्म का हुनर है।

गुण क्या हो?

इस प्रोफेशन में भी करियर बनाने के लिए कुछ विशेष गुणों की दरकार है। सबसे पहले उसमें विजुअलाइजेशन की क्षमता होनी चाहिए कि कौन सा स्टाइल या गेटअप किस पर फबेगा। उसे ऐसा रूप देना कि खुद को देख कर उसमें आत्मविश्वास भर जाए। कभी-कभी कई घंटों तक काम करना होता है, खासकर टीवी और फिल्म की शूटिंग के दौरान। शारीरिक और मानसिक रूप से उसका फिट होना बहुत जरूरी है, तभी वह अपने काम को सही-सही अंजाम दे पाएगा। आप में रंग और उसके असर की बारीक समझ होनी चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आपका व्यवहार दोस्ताना होना चाहिए, तभी जिसका आप मेकअप करने जा रहे हैं, उसे बिना उबाए या थकाए उसका मनपसंद गेटअप आप उसे दे पाएंगे। इसके अलावा खुद भी आकर्षक दिखना जरूरी है। फैशन इंडस्ट्री में स्टाइल और ट्रैंड रोज बदलते हैं, इसलिए नई-नई तकनीक, हेयरस्टाइल्स और कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट के बारे में उसे अपडेट रहना होगा।

योग्यता क्या हो?

मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है और न ही किसी प्रकार की योग्यता की। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने स्कूल या कॉलेज में कौन सा विषय लिया था। बस आप में इस काम के प्रति लगाव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके लिए करियर की राहें आसान हैं। अगर 10वीं या 12वीं पास हैं तो और भी बेहतर।

इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आप ब्यूटीकेयर के अंतर्गत अन्य विषयों जैसे ब्यूटीशियन, मैनिक्यूरिस्ट, पैडिक्यूरिस्ट, इलेक्ट्रोलॉजिस्ट व अरोमा थेरेपी विषयों में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी संस्थान से भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। संस्थानों द्वारा संचालित कोर्सेज के पाठयक्रम में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डाइट, सेल्समैनशिप व सैलून आर्गेनाइजेशन से संबंधित थ्योरी पढ़ाई जाती है। वहीं प्रैक्टिकल वर्क के रूप में फेशियल, डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज, मेकअप व इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट सिखाया जाता है।

नौकरी के अवसर

वर्तमान में फिल्म व टेलीविजन इंडस्ट्री में मेकअप व हेयर ड्रेसिंग एक्सपर्ट की मांग बढ़ती जा रही है। इन एक्सपर्ट्स को फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है। बतौर फ्रीलांस भी इसमें हैं ढेरों काम। फैशन आर्गेनाइजर, ब्यूटी पार्लरों, सिलेब्रिटीज के लिए बड़े पैमाने पर काम है।

वेतन

इस क्षेत्र में आने वाले को बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के दौरान ही आपकी कमाई होने लगती है। शुरुआती सैलरी 8 से 10 हजार मिलती है, लेकिन 5 साल के भीतर आप हर महीने 30 हजार रुपये तक कमा सकते हैं। एक बार आपका नाम हो गया तो आकाश ही सीमा है। कुछ कलाकार साल में 5 लाख रुपये या इससे अधिक भी कमा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ विज्ञापन एजेंसी द्वारा शुरू की गई कैंपेन में एक दिन में ही आपकी कमाई 1500 से 3000 रुपये तक हो सकती है।

कहां-कहां हैं मौके?



फिल्म/ टीवी/ वीडियो/ रंगमंच/ फैशन/ विज्ञापन एजेंसियों में तो बेशुमार जॉब हैं ही, तेजी से खुल रहे न्यूज चैनलों में भी मेकअप आर्टिस्ट की डिमांड है। वर्तमान में फिल्म व टेलीविजन इंडस्ट्री में मेकअप व हेयर ड्रेसिंग एक्सपर्ट की मांग बढ़ती जा रही है। इन एक्सपर्ट्स को फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि स्टूडियो की चकाचौंध लाइट में एक्टर का मेकअप कैसे किया जाता है। बतौर फ्रीलांस भी इसमें हैं ढेरों काम। फैशन आर्गेनाइजर, ब्यूटी पार्लरों, सिलेब्रिटीज के लिए बड़े पैमाने पर काम है।



यूपीएससी हर साल सिविल सेवा में परीक्षा का आयोजन करता है। इनमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस पदों के लिए सबसे ज्यादा दावेदार होते हैं। इस परीक्षा को क्रैक कर आईएएस की तरह आईएफएस अफसर बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एक आईएएस जहां देश के अंदर कार्य करता है, वहीं एक आईएफएस ऑफिसर दूसरे देशों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। इस आर्टिकल के माध्यम से आज हम जानेंगे कि आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए और इनका क्या काम होता है।

कौन और कैसे बन सकते हैं आईएफएस ऑफिसर

आईएफएस स्तर का अधिकारी देश का प्रतिनिधित्व अनेकों अंतर्राष्ट्रीय मंचो पर करता है। इनका दायरा एक आईएएस ऑफिसर से बड़ा होता है। क्योंकि जहां एक आईएएस जिले व देश तक सीमित होते हैं, वहीं एक आईएफएस देश स्तर पर अधिकारिक रूप में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओ और देशों के साथ काम करते हैं। इनके काम का असर सीधा देश पर पड़ता है। आईएफएस के लिए भी उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होता है, लेकिन आईएफएस की मुख्य परीक्षा का सिलेबस अन्य परीक्षाओं से अलग होता है। आईएफएस में आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक आईएफएस ऑफिसर विभिन्न देशो के राजदूत, अधिकारी व नेताओं से बात करनी होती है तो इसके लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और बोलचाल में जरूरत होती है।

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

राष्ट्रीयता

आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवार की राष्ट्रीयता निम्नलिखित होनी चाहिए

- भारत के नागरिक हो
- नेपाल/भूटान की नागरिक हो
- वे तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पहले स्थायी रूप से बसने के लिए यहाँ आए, या
- भारतीय मूल के वे लोग जिन्होंने भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए युगांडा, बर्मा, पाकिस्तान, जाम्बिया, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, मलावी, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवास किया।

शैक्षणिक योग्यता

- उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

आयु सीमा

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आधिकारिक अधिसूचना में यूपीएससी आयु सीमा 2022 की जानकारी जारी की गई है। आयु सीमा पात्रता मानदंड के अनुसार, 1 अगस्त 2022 को 21 से 32 वर्ष के बीच की आयु के लोग यूपीएससी एग्जाम में आवेदन पत्र भर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के आवेदक यूपीएससी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आयु में छूट के पात्र होते हैं।

- एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए- 5 साल
- ओबीसी उम्मीदवारों के लिए- 3 साल।
- जम्मू और कश्मीर राज्य के उम्मीदवार के लिए- 5 वर्ष
- रक्षा सेवा कर्मियों के लिए- 5 वर्ष
- पूर्व सैनिक जिनमें कमीशन अधिकारी और ईसीओ/एसएससीओ शामिल हैं, जिन्होंने कम से कम 5 साल की सैन्य सेवा प्रदान की है और उन्हें रिहा कर दिया गया- 5 वर्ष
- नेत्रहीन, मूक-बधिर और विकलांग व्यक्तियों के लिए- 10 वर्ष

उम्मीदवार कितनी बार दे सकते हैं ये एग्जाम

- सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार- 6 प्रयास
- एससी / एसटी के उम्मीदवार- कोई प्रतिबंध नहीं
- अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार- 9 प्रयास
- सामान्य व ओबीसी दिव्यांग- 9 प्रयास

मेडिकल स्टैंडर्ड

इस परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले आवेदकों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यूपीएससी सीएसई पर्सनालिटी टेस्ट के बाद चुने गए उम्मीदवार यूपीएससी द्वारा अधिसूचित चिकित्सा केंद्र में मेडिकल टेस्ट से गुजरते हैं। किसी भी सेवा में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को सभी मेडिकल टेस्ट पास करना होता है।

आईएफएस के कार्य

एक आईएफएस का काम उसके उसकी प्रोफाइल पर निर्भर करता है। विदेश में रह रहे भारतीयों की मदद वहां का भारतीय दूतावास करता है, जोकि एक आईएफएस का कार्य होता है। यही ऑफिसर राजदूत और राजनयिक के रूप में भी कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य दोनों देशो के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना और अन्य किसी प्रकार के वाद-विवाद को भी बातचीत के जरिए हल करना है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यूनाइटेड नेशन व अन्य प्लेटफार्म आईएफएस अधिकारी ही विदेशी मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही भारत की सुरक्षा व विदेशी नीति मामलों में भी इन्ही आईएफएस की मदद ली जाती है और ये अपने अनुभव से देश की विदेश सुरक्षा पॉलिसी में अपने विचार व ज्ञान का उपयोग करते हैं।





ऑडियो इंजीनियरिंग
नई पीढ़ी का उभरता हुआ करियर

एक समय ऐसा था, जब आवाज को उसके मूल रूप में ही रिकॉर्ड किया जाता था, परन्तु आज उसमें काफी हद तक बदलाव लाया जा सकता है। यह सब संभव हो पाया है 'ऑडियो इंजीनियरिंग' से। वैसे तो आवाज या म्युजिक का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन 20वीं शताब्दी तक आते-आते उसमें कई चीजें जुड़ गई। ऑडियो इंजीनियरिंग, ऑडियो साइंस की ही एक शाखा है। इसमें साउंड कैप्चर करने, रिकॉर्डिंग करने, कॉपी करने, एडिटिंग एवं मिक्सिंग करने, इलेक्ट्रॉनिक एवं मैकेनिकल उपकरणों द्वारा आवाज में उतार-चढ़ाव लाने संबंधी कार्य किए जाते हैं। यह पूरा कार्य पोस्ट प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मिक्सिंग बोर्ड लगा होता है, जिससे रिकॉर्डिंग एवं एडिटिंग प्रक्रिया में साउंड इनपुट जैसे स्विच, डायल, लाइट्स एवं मीटर को नियंत्रित किया जाता है। यह कार्य ऑडियो इंजीनियर के जरिए संपन्न किया जाता है। कई बार इन्हें रिकॉर्डिंग इंजीनियर या साउंड इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है। ऑडियो इंजीनियरिंग नई पीढ़ी के लिए एक उभरता हुआ करियर है, जो भारत एवं विदेश दोनों जगह फिल्म, वीडियो प्रोडक्शन, साउंड ब्रॉडकास्टिंग एवं एडवर्टाइजिंग में संभावनाएं तलाशता है। इस फील्ड के लिए खुद से कमिटमेंट एवं इंटरेस्ट होना आवश्यक है।

ऑडियो इंजीनियरिंग भारत एवं विदेश दोनों जगह फिल्म, वीडियो प्रोडक्शन, साउंड ब्रॉडकास्टिंग एवं एडवर्टाइजिंग में संभावनाएं तलाशता है। इस फील्ड के लिए खुद से कमिटमेंट एवं इंटरेस्ट होना आवश्यक है।

म्युजिक, साउंड रिकॉर्डिंग, म्युजिक बिजनेस, मल्टीट्रैक प्रोडक्शन आदि कई ऐसे एरिया हैं, जिन्हें ऑडियो इंजीनियरिंग के तहत शामिल किया जाता है।

क्वालिफिकेशन

एक सफल ऑडियो इंजीनियर बनने के लिए ऑडियोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग एवं ऑडियो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा डिग्री कोर्स का होना आवश्यक है। वैसे तो इस फील्ड में किसी विशेष शैक्षिक योग्यता की दरकार नहीं होती, परन्तु ऑडियो इंजीनियरिंग में बैचलर अथवा पीजी डिग्री को वरीयता दी जाती है। जहां तक डिमांड की बात है तो ऑडियो इंजीनियर बनने के लिए फिजिक्स अथवा मैथ्स की आधारभूत जानकारी सहायक साबित होती है, जिसके दम पर वे रिकॉर्डिंग रूम में कई तरह की प्रतिध्वनि का आकलन कर सकते हैं। इसमें अधिक प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार पर एक अच्छा ऑडियो इंजीनियर बना जा सकता है। जिन छात्रों के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं फाइन आर्ट की पृष्ठभूमि रही है, वे भी इस कोर्स के लिए उपयुक्त साबित हो सकते हैं। साथ ही उन्हें रिकॉर्डिंग उपकरणों जैसे मिक्सिंग कंसोल्ड एवं माइक्रोफोन की जानकारी भी होनी चाहिए। इस कार्य में उन्हें डिजिटल ऑडियो स्टेशन, स्पीकर, एंप्लीफायर सहित कई अन्य म्युजिक उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है।

कोर्स डिटेल्स

ऑडियो इंजीनियरिंग में साउंड रिकॉर्डिंग, एडिटिंग एवं मिक्सिंग के तकनीकी एवं रचनात्मक पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। इसमें अधिकतर कोर्स की शुरुआत ही साउंड एवं रिकार्डिंग, पोस्ट प्रोडक्शन एवं ब्रॉडकास्टिंग की आधारभूत थ्योरी एवं फिक्केंसी से की जाती है। इसके तकनीकी पहलुओं के अंतर्गत ही साउंड मिक्सिंग में स्पेशल इफेक्ट्स डाला जाता है। कोर्स के बाद छात्र रिकॉर्डिंग टूल्स, माइक्रोफोन के प्रयोग के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ हो जाते हैं। इसके अलावा ऑडियो राइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक

पर्सनल स्किल्स

एक ऑडियो इंजीनियर को टेक्निकल नॉलेज, इलेक्ट्रिकल एप्टीट्यूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल सिस्टम एवं इक्विपमेंट की जानकारी होनी आवश्यक है। म्यूजिक प्रोडक्शन में टीम वर्क, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके काम को गति दे सकते हैं। एकाग्रता, धैर्य, अच्छी समझ, अच्छी लय की जरूरत, अच्छी रिद्म जैसे गुण ऑडियो इंजीनियर के लिए आवश्यक हैं। साथ ही उसे रिकॉर्डिंग माध्यमों जैसे एनालॉग टेप, डिजिटल मल्टीट्रैक रिकॉर्डर एवं कम्प्यूटर नॉलेज की जानकारी भी सहायता दिला सकती है।

नौकरी के अवसर

इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए ऑडियो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री पहली सीढ़ी होती है। सफलतापूर्वक कोर्स करने के बाद मूवी, टेलीविजन, एडवर्टाइजिंग, मल्टीमीडिया संस्थान, ब्रॉडकास्टिंग, सीडी प्रोडक्शन आदि में जॉब पा सकते हैं। लेकिन एक ऑडियो इंजीनियर को जो फील्ड सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, वह म्युजिक इंडस्ट्री है। इसमें प्रारंभ में रिकॉर्डिंग इंजीनियर के सहायक के रूप में करियर आरंभ कर सकते हैं। अपने अनुभव के आधार पर जल्द ही वे ऑडियो इंजीनियर के पद पर पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त माइक्रोफोन, रिकॉर्डर, मिक्सर एवं सॉफ्टवेयर, म्युजिक एवं स्पीच में कई तरह के काम सामने आते हैं। साउंड, म्युजिक, डायलॉग, स्पेशल इफेक्ट्स, म्युजिक प्रोड्यूसर को भी स्पेशलाइजेशन के रूप में अपनाया जा सकता है। म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने के बाद खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी शुरू किया जा सकता है। स्टूडियो स्थापित करने के अलावा ऑडियो इंजीनियर फ्रीलांस के रूप में भी काम कर सकते हैं। ऑडियो इंजीनियरिंग का क्षेत्र काफी प्रतियोगी है। इसमें वही लोग सफल हो सकते हैं, जिनमें टैलेंट एवं विशेष गुण है।

सेलरी स्ट्रक्चर

बतौर ऑडियो इंजीनियर इनकी सेलरी 10,000 रुपए प्रतिमाह से शुरू होती है तथा मान्यता मिल जाने के बाद इनकी सेलरी में तेजी से इजाफा होता है। तीन से चार साल के अनुभव के बाद इनकी सेलरी 30-35 हजार रुपए तक पहुंच जाती है। विदेशों में जॉब के अवसर मिलने के बाद सेलरी की कोई निश्चित सीमा नहीं होती।



राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सीजेपी बनी आप की बी टीम और एसआईआर पर फैलाया भ्रम



नईदिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हालिया विरोध प्रदर्शनों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी पर सवाल उठाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, बीजेपी नेता ने सवाल उठाया कि क्या दबाव समूह ने दूसरे राज्यों के मुद्दों पर भी बात की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि यह हैरानी की बात है कि स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (एसआईआर) पर इस तरह सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि देश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग ने पिछले कई सालों में कई बार इस तरह का रिविज़न किया है। चाहे राज्य में कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो या केंद्र में, यही तरीका अपनाया जाता रहा है। पहले इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? अब ऐसी आपत्तियां क्यों उठाई जा रही हैं? उन्होंने सीजेपी पर भी निशाना साधा और भाजपा के इस दावे को दोहराया कि यह प्रेशर ग्रुप आम आदमी पार्टी की बी-टीम है।

सौरव दास और आशुतोष रांका 5 दिन की न्यायिक हिरासत में



नईदिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बांड का कथित उल्लंघन करने और जंतर-मंतर में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के आरोप में बुधवार को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से बाहर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि सौरव दास और आशुतोष रांका को तिहाड़ जेल में रखा गया है। उनके सहयोगी अजिंक्य शिंदे को छह महीने तक शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार करने के लिए पांच हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर पाबंद कर रिहा कर दिया गया। तीनों को बुधवार सुबह विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। कॉजपा नेताओं को मंगलवार तड़के हिरासत में लिया गया था। उन पर बैरिकेड तोड़कर बिना अनुमति जंतर-मंतर क्षेत्र में प्रवेश करने का आरोप है।

सीजेपी नेताओं के समर्थन में उतरे राहुल गांधी



नईदिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका को जेल भेजे जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस कार्रवाई को कायरतापूर्ण हरकत करार देते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना कोई अपराध नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि जंतर-मंतर को हर हाल में वापस हासिल किया जाएगा। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में राहुल ने कहा, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना कोई अपराध नहीं है। इसके लिए युवाओं को जेल भेजना कायरतापूर्ण हरकत है। उन्होंने आगे कहा, छात्र। युवा। पत्रकार। इंडिया गठबंधन। अलग-अलग बैनर, एक मकसद। सभी विरोध प्रदर्शन एक ही हैं: नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि जंतर-मंतर भारत के लोगों का है और हम इसे वापस हासिल करेंगे।

कांग्रेस की पुनः मजबूती से बैकफुट पर भाजपा : तिवारी



नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लंबे समय की चुप्पी के बाद बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी फिर से मज़बूत हो रही है। अमित शाह की उस टिप्पणी का जवाब देते हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (एसआईआर) में सहयोग न करके विपक्ष अवैध घुसपैठियों को बचाना चाहता है, तिवारी ने पार्टी के पुनरुद्धार के सबूत के तौर पर चार राज्यों में पार्टी की स्थिति का ज़िक्र किया। तिवारी ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि अमित शाह, जो इतने लंबे समय से चुप थे, उन्हें मंगलवार को सामने आना पड़ा। शायद उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। 1985 में मैंने अपनी आँखों से देखा था कि संसद में बीजेपी के दो सांसद थे। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में दहाई का आँकड़ा भी नहीं छू पाए थे। कांग्रेस अब वापसी की राह पर है। जिस दिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव होंगे, वहाँ कांग्रेस के नेतृत्व में तिरंगा लहराएगा।

एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी



नई दिल्ली। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया। इस याचिका में चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में सुधार की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) प्रक्रिया के तरीके को चुनौती दी। इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए वोटर डेटाबेस और नामों को हटाने की प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग की थी। विपक्ष की याचिका में वोटर डेटाबेस और नामों को हटाने की प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट कराने के साथ-साथ, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की मांग की गई है। यह कमेटी सुधार प्रक्रिया के लागू होने और वोटर लिस्ट व इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (इवीएम) से जुड़े तकनीकी सिस्टम की जांच करेगी।

दुनिया भर में मिल रही भारतीय संस्कृति को पहचान : मोदी

प्रधानमंत्री बोले- प्राचीन धरोहरों की वापसी के प्रयास तेज



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार पहचान मिल रही है। भारत का संगीत, नृत्य, सिनेमा और खानपान दुनिया के अलग-अलग देशों के लोगों को भारत से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यह बात 'बृहत्तर भारत: दुनिया भर में भारत के सांस्कृतिक संबंध' विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भेजे गए अपने लिखित संदेश में कही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सरकार केवल ऐतिहासिक स्मारकों को सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की प्राचीन पांडुलिपियों को भी सहेजने के प्रयास कर रही है। इसके लिए ज्ञान भारतम पहल के तहत काम किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य भारत की पांडुलिपियों से जुड़ी विरासत को संरक्षित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि दूसरे देशों में मौजूद भारत की प्राचीन धरोहरों को वापस लाने के प्रयासों को नई गति मिली है।

ऐतिहासिक स्मारकों को सुरक्षित रखने के साथ भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को सहेजने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ज्ञान भारतम पहल के जरिए पांडुलिपियों से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विदेशों में मौजूद भारत की प्राचीन धरोहरों को वापस लाने के प्रयासों में भी नई तेजी आई है।

यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 14 से 16 अक्तूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) कर रहा है। सम्मेलन में भारत की सांस्कृतिक विरासत और देश के दूसरे समाजों व सभ्यताओं के साथ उसके संबंधों पर चर्चा हो रही है। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री का लिखित संदेश केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने पढ़कर सुनाया।

एशियाड के पदकवीरों से आज मिलेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को हाल ही में संपन्न हुए आइची-नागोया एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और सहयोगी स्टाफ से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्यक्रम दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम करीब 4:30 बजे आयोजित होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे।

आइची-नागोया एशियन गेम्स में भारत ने कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में शीर्ष पांच देशों में शामिल रहा। हालांकि, इस बार भारतीय दल का प्रदर्शन पदकों की संख्या के लिहाज से पिछले संस्करण से पीछे रहा। वर्ष

अखिलेश यादव को बड़ा झटका

समाजवादी पार्टी के तीन बागी विधायक भाजपा में शामिल



लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है क्योंकि पार्टी के तीन विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये तीन बागी विधायक हैं - राकेश प्रताप सिंह (गौरीगंज), अभय सिंह (गोसाईंगंज) और विनोद चतुर्वेदी (कालपी)। राकेश प्रताप सिंह अमेठी की गौरीगंज सीट से, अभय सिंह अयोध्या की गोसाईंगंज सीट से और विनोद चतुर्वेदी जालौन की कालपी विधानसभा सीट से विधायक हैं। इन विधायकों ने 2022 का चुनाव सपा के टिकट पर जीता था, लेकिन 2024 के राज्यसभा चुनाव में इन्होंने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया।

अभय सिंह ने भाजपा में शामिल होने पर कहा कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विरोध करें, जो राष्ट्र का विरोध करेंगे, हम लोग उसके विरोधी हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में जन-जन तक हिंदी और अवधि में पहुंचाने वाले, तुलसीदास ने राम चरित मानस को लिखा। उस रामचरित मानस को जलाया जाए, फाड़ा जाए। उसके बाद इस घटना पर कोई टिप्पणी न की जाए। उसके बाद दर्शन से रोका जाए। ये सब चीजें ऐसी हैं जो उचित नहीं हैं।

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर कहा कि भाजपा की नीतियां और मोदी-योगी की सेवाओं के बलबूते, आम जनमानस से लेकर जनप्रतिनिधियों तक में उत्साह है और सब भाजपा की ओर आकर्षित हैं, आना चाहते हैं। विनोद चतुर्वेदी ने भाजपा में शामिल होने पर कहा कि जब पीएम मोदी ने भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन किया तो सदन में हमारे अध्यक्ष ने कहा था कि दर्शन के लिए जो भी चलना चाहे, वो चले लेकिन हमारे हाईकमान ने कहा कि नहीं। ये आस्था पर चोट थी। दूसरा, योगी आदित्यनाथ ने जैसा विकास किया है, वैसा विकास किसी ने नहीं किया। जनता को विकास चाहिए और हम उस विकास के लिए ही चुने जाते हैं। जिस सरकार ने इतना विकास किया है, हम उसके साथ हैं।

विधायक राकेश प्रताप सिंह ने उनके भाजपा में शामिल होने पर कहा कि मैं अपने क्षेत्रवासियों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारा समर्थन किया और मुझसे अनुरोध किया कि भाजपा की सदस्यता लीजिए। उन लोगों ने मुझसे कहा कि वे मेरे साथ हैं... 98% लोग जो अपना बूथ जिताते या हराते थे, वे समाजवादी पार्टी का परित्याग करेंगे और भाजपा की सदस्यता लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि विधायक विनोद चतुर्वेदी, अभय सिंह और मैं स्वयं भाजपा में शामिल हो रहा हूं।

एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर कथित लाठीचार्ज

भारत की आवाज दबा नहीं सकते : राहुल गांधी



नईदिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई से जुड़े कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस द्वारा कथित तौर पर पिटाई किए जाने को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि दोनों नेता ''भारत की आवाज'' के खिलाफ खड़े हैं। राहुल गांधी कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ मीडिया से मुखातिब हुए, जिन्हें दिल्ली में मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित तौर पर पीटे जाने के कारण चोट आई है। गांधी ने इन छात्रों की ओर इशारा करते हुए संवाददाताओं से कहा, ''जैसा कि मैंने अपनी प्रेस वार्ता में कहा था, अपने चारों ओर देखिए।

यह भारत है। अमित शाह जी, इसे ध्यान से देखिए।'' उन्होंने कहा, ''यहां कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई जाति, कोई महिला या कुछ और नहीं है। यहां सिर्फ एक आवाज, एक विरोध है और वह भारत की आवाज है।'' लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने गृह मंत्री को संबोधित करते हुए कहा, ''आप इस आवाज के खिलाफ खड़े हैं।

प्रधानमंत्री भी इस आवाज के खिलाफ खड़े हैं। मेरी आपको सलाह है कि इसके खिलाफ खड़े न हों। इस आवाज के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता।'' गांधी ने इस दौरान केरल की निवासी और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा आथिरा का उल्लेख करते हुए दावा किया कि पुलिस कार्रवाई के कारण उसके एक कान की सुनने की क्षमता चली गई है।

उन्होंने कहा, ''केरल की आथिरा के एक कान की सुनने की क्षमता चली गई है। उसके कान पर चोट मारी गई थी और अब वह उस कान से सुन नहीं सकती।'' कांग्रेस नेता ने कहा, ''पिछली बार मैंने आपको एक लड़का दिखाया था जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। अब आथिरा एक कान से सुन नहीं सकती।'' आथिरा ने आरोप लगाया कि मंगलवार को जब प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया तो जिस बस में उन्हें ले जाया गया, उसमें कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी।

छात्रा के मुताबिक, उसने पुलिसकर्मियों से सवाल किया कि महिला पुलिस अधिकारी या महिला कांस्टेबल कहां हैं क्योंकि हिरासत में लेने की स्थिति में कम से कम एक महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी जरूरी है। अथिरा ने आरोप लगाया कि इसके बाद बस चली और कनॉट प्लेस पुलिस थाने के सामने रुकी, जहां उसके चेहरे पर मारा गया। उसने कहा, ''इसकी वजह से मेरी आंख में चोट लगी है और कान को भी नुकसान पहुंचा है।'' गांधी ने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि वह उनसे ''प्यार और दिल से'' एक बात कहना चाहते हैं कि उन्होंने सभी छात्रों से घटनाओं के वीडियो बनाने और साक्ष्य सुरक्षित रखने को कहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा, ''मैं हर छात्र से वीडियो बनाने और हमें भी साक्ष्य भेजने को कह रहा हूं। जब यह पूरा मामला खत्म होगा तो हम सभी साक्ष्यों का इस्तेमाल करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जो जवाबदेह हैं, उन्हें दंडित किया जाए।''

खेल
प्रमुख समाचार

न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया के ऐलान में देरी



नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की चयन समिति न्यूजीलैंड दौरे के लिए वनडे और टेस्ट टीम का ऐलान करने से पहले तीन अहम खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा, ऑलराउंडर हर्षित राणा और विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की चोटों के कारण टीम चयन में देरी हो रही है।

भारत का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज से शुरू होगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टी20 टीम का ऐलान पहले ही किया जा चुका है, जबकि वनडे और टेस्ट टीमों की घोषणा बाकी है। वनडे सीरीज 4 नवंबर से ऑकलैंड में शुरू होगी, जबकि दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 19 नवंबर को वेलिंगटन में होगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, चयनकर्ता प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और ऋषभ पंत की चोट से उबरने की प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इन तीनों खिलाड़ियों की उपलब्धता वनडे और टेस्ट टीम के संयोजन को प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से चयनकर्ता अंतिम फैसला लेने से पहले मेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।

तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर हर्षित राणा जुलाई से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। वह निचले मध्यक्रम में बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी योगदान दे सकते हैं, इसलिए चयनकर्ता उन्हें वनडे और टेस्ट दोनों टीमों में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, उनकी वापसी पूरी तरह फिटनेस पर निर्भर करेगी। प्रसिद्ध कृष्णा की तरह ऋषभ पंत को भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करने के बाद तीन सप्ताह की रिकवरी अवधि दी गई थी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 251 अंक और निफ्टी 99 अंक लुढ़का

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में 14 अक्तूबर 2026 को प्रमुख सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए। बाजार के बंद होने के समय दोनों सूचकांकों में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। बीएसई सेंसेक्स का कारोबारी दिन 72,781.89 के स्तर पर समाप्त हुआ। यह सूचकांक 251.89 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। प्रतिशत के संदर्भ में, इसमें 0.34 फीसदी की कमी दर्ज की गई। एनएसई निफ्टी 50 भी गिरावट के साथ 22,622.70 के स्तर पर बंद हुआ। इसमें 99.25 अंकों की कमी आई, जो 0.44 फीसदी रही। सेंसेक्स का पिछला बंद भाव 73,033.78 था। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे की बढ़त के साथ 95.15 (अस्थायी) के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 73,195.26 का उच्चतम स्तर छुआ।

खाने-पीने से लेकर ईंधन तक महंगाई की मार

नई दिल्ली। खाद्य पदार्थों, विनिर्मित वस्तुओं और ईंधन एवं बिजली की कीमतें बढ़ने से सितंबर में थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 11.39 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त में 9.92 प्रतिशत थी। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर अगस्त के 7.05 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 8.66 प्रतिशत हो गई। विनिर्मित वस्तुओं में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 9.76 प्रतिशत के श्रृंखला के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। ईंधन एवं बिजली की महंगाई दर सितंबर में 25.85 प्रतिशत रही, जबकि पिछले महीने यह 22.93 प्रतिशत थी। इस सप्ताह की शुरुआत में जारी खुदरा महंगाई के आंकड़ों के अनुसार, खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण सितंबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 23 महीने के उच्च स्तर 5.54 प्रतिशत पर पहुंच गई।

ब्लैकस्टोन भारत में अपना निवेश बड़े पैमाने पर बढ़ाने की तैयारी

नई दिल्ली। दुनिया की प्रमुख अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल ब्लैकस्टोन भारत में अपना निवेश बड़े पैमाने पर बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी अगले पांच वर्षों में भारत में अपने निवेश को मौजूदा 50 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहती है। ब्लैकस्टोन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जोनाथन ग्रे ने एक इंटरव्यू में यह जानकारी दी। कंपनी की योजना प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट और ग्रोथ इक्विटी जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की है। जोनाथन ग्रे के मुताबिक, भारत में लंबी अवधि के विकास की संभावनाएं मजबूत हैं। देश का बढ़ता मध्य वर्ग और मजबूत होते पूंजी बाजार विदेशी निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। इसी को देखते हुए ब्लैकस्टोन अगले पांच साल में अपने भारतीय निवेश को दोगुना करने की रणनीति पर काम कर रही है।

तेल के सबसे बड़े आयातक देश ने दबाया 'रेड बटन'

टोक्यो। एशिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में शामिल जापान ने तेल संकट की आशंका के बीच 'रेड अलर्ट' जारी करते हुए एशियाई देशों से अपने आपातकालीन तेल भंडार मजबूत करने की अपील की है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल आपूर्ति बाधित होने के खतरे को देखते हुए जापान ने चेताया है कि संकट गहराने से पहले तेल के टैंक भरकर रखना जरूरी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जापान ने एशियाई देशों से अपने आपातकालीन तेल भंडार मजबूत करने की अपील की है। जापान के उद्योग मंत्री योंसेई अकाजावा ने तेल उत्पादक देशों और आयातक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है।

स्टारलिंक : सैटेलाइट इंटरनेट पर भारतीय कानूनों का पहरा जरूरी

आर जगन्नाथन

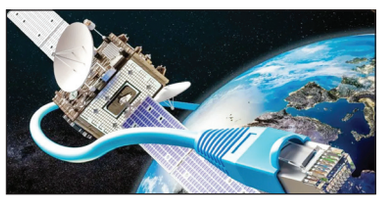
गत 8 अक्टूबर को स्पेसएक्स के मालिक ईलॉन मस्क ने दावा किया कि भारत के ओलिगार्क (अति धनाढ्य कुलीन वर्ग) उनकी स्टारलिंक सैटेलाइट फोन सेवाओं को रोक रहे हैं। खुद मस्क को टेक क्षेत्र के अरबपतियों में 'सुपर-ओलिगार्क' कहा जा सकता है। शायद 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' कहावत ऐसे ही मौकों के लिए बनी है।

उन्होंने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, 'दुर्भाग्य से कुछ ओलिगार्क हमें रोक रहे हैं ताकि भारतीय लोगों पर अपनी एकाधिकारवादी पकड़ बनाए रख सकें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कौन हैं। यह भारत के लोगों के खिलाफ अपराध है।' मस्क से जुड़े एक एक्स अकाउंट ने यह भी कहा कि मई 2026 तक 11,256 से अधिक गांवों में 4जी सेवाएं तक उपलब्ध नहीं हैं।

इस समय 'वोट चोरी' के खिलाफ प्रदर्शन में लगे राहुल गांधी ने भी मस्क के दावे का समर्थन करते हुए 'वेलकम टु इंडिया' पोस्ट कर दिया। कोई भारतीय राजनेता कहीं अधिक ताकतवर विदेशी ओलिगार्क के पक्ष में उससे कहीं कम ताकतवर भारतीय ओलिगार्कों के खिलाफ मोर्चा संभाले, शायद इस वक्त इसकी जरूरत नहीं।

मस्क की बात वास्तविकता से काफी दूर है। स्टारलिंक का मुख्य विरोध जियो के मुकेश अंबानी या भारती एयरटेल के सुनील मित्तल की ओर से नहीं भारत सरकार की ओर से है। सरकार इस बात को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है कि ऐसे संगठनों को हजारों की संख्या में सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराने से सुरक्षा संबंधी क्या परिणाम हो सकते हैं जो भारत के हितों के खिलाफ काम करते हों।

जब स्टारलिंक ने भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की मंशा जाहिर की थी तब उसके



साथ साझेदारी करने वाले पहले कारोबारी वही ओलिगार्क थे जिनके खिलाफ मस्क अब आरोप लगा रहे हैं। मोदी सरकार ने एकाधिकार जैसी स्थिति बनने से रोकने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और वोडाफोन दोनों को बचाये रखने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये दिए हैं या उनका कर्ज माफ किया है।

अगर मस्क वास्तव में भारत के अंतिम व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाने के लिए इतने उत्सुक होते तो वह आसानी से खुद वोडाफोन को आर्थिक मदद देकर बचा सकते थे और भारतीय दूरसंचार व्यवस्था में अपनी मजबूत जगह बना सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह भारतीय बाजार में पैसा कमाने के साथ-साथ राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए भी प्रवेश करना चाहते हैं। एक्स, ग्रोक और स्टारलिंक के जरिये वह भारतीय राजनीति को प्रभावित करने की बेहद शक्तिशाली स्थिति में होंगे।

शुरुआती दौर में सैटेलाइट संचार का बाजार बहुत छोटा रहने की संभावना है। विदेशी सैटकॉम कंपनियों को भारत में सेवा की अनुमति देने के पीछे तर्क यह है कि देश के अंदरूनी और पहाड़ी इलाकों में नियमित दूरसंचार सेवाएं या तो बहुत खराब हैं या बिल्कुल उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन अगर यह मान लिया जाए कि इन इलाकों में रहने वाले लोग गरीब भी हैं तो ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान करने वाला बाजार भी कमजोर रहने की संभावना है। कम से कम शुरुआती वर्षों में। सैटेलाइट संचार सेवाओं का वास्तविक बाजार, जिसमें सैटेलाइट से सीधे मोबाइल फोन तक इंटरनेट पहुंचाने वाली सेवाएं भी शामिल हैं, क्रमशः इस तरह उभरेगा- सबसे पहले राज्य, यानी सशस्त्र बल, केंद्रीय और राज्य पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी, इसके बाद राजनेता, कारोबारी, शहरी अमीर और मध्यम वर्ग। इनमें से अंतिम चार वर्गों को, जिनमें ज्यादातर शहरी लोग हैं, सैटेलाइट फोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले से ब्रॉडबैंड वाई-फाई और 5जी सेवाएं उपलब्ध हैं।

इस श्रेणी के लिए सैटेलाइट फोन दिखावे की खरीद हो सकता है। लेकिन तस्कर और असामाजिक तत्व तत्काल सैटेलाइट फोन रखना चाहेंगे। यह दावा हास्यास्पद है कि सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल पहाड़ों के गरीब लोग करेंगे। अमीर हमेशा गरीबों की मदद के तर्क का सहारा लेकर अपने हितों को उचित ठहराते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की बड़ी सौगात

जशपुरनगर में 11.83 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा हाईटेक बस स्टैंड

कुनकुरी और पत्थलगांव में भी आधुनिक बस स्टैंड को स्वीकृति, बंदरचुआ और दुलदुला में निर्माण कार्य जारी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में यात्री सुविधाओं के विस्तार और सार्वजनिक परिवहन अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर जिला मुख्यालय जशपुरनगर में 11 करोड़ 83 लाख 62 हजार रुपये की लागत से हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया जारी है। लगभग तीन एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह आधुनिक बस टर्मिनल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ शहर की परिवहन व्यवस्था को नया स्वरूप देगा। लंबे समय से आधुनिक बस स्टैंड की प्रतीक्षा कर रहे जिलेवासियों के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण सौगात साबित होगी।

जशपुरनगर के वार्ड क्रमांक 8 स्थित पुराने मवेशी बाजार परिसर में हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण प्रस्तावित है। लगभग तीन एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाले इस आधुनिक बस टर्मिनल में एक साथ 35 से 40 बसों के खड़े होने की व्यवस्था होगी। इससे बसों के आवागमन और ठहराव को व्यवस्थित करने के साथ यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

जशपुर जिला मुख्यालय का बस स्टैंड जिले के प्रमुख परिवहन केंद्रों में शामिल है। यहां प्रतिदिन 100 से अधिक बसों का आवागमन होता है और पांच हजार से अधिक यात्री सफर करते हैं। यहां से जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अलावा पड़ोसी राज्यों झारखंड, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित अन्य स्थानों के लिए बस सेवाएं संचालित होती हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस



स्टैंड की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। नए बस स्टैंड के निर्माण से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी।

प्रस्तावित हाईटेक बस स्टैंड को यात्रियों की सुविधा और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। यहां आधुनिक यात्री प्रतीक्षालय, सुव्यवस्थित वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर, लिफ्ट और आधुनिक शौचालय सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

'कुनकुरी और पत्थलगांव में भी बनेंगे आधुनिक बस स्टैंड'

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के विभिन्न नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। जशपुरनगर के साथ कुनकुरी और पत्थलगांव में भी अत्याधुनिक बस स्टैंड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसी क्रम में बंदरचुआ और दुलदुला में एक-एक करोड़ रुपये की लागत से बस स्टैंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से जिले में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी। जशपुरनगर में प्रस्तावित हाईटेक बस स्टैंड सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित की जा रही परिवहन अधोसंरचना से आने वाले समय में यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा तथा स्थानीय व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल होने पर किसानों में उत्साह एवं खुशी

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को शक्कर की बोरियों से तौलकर जताया आभार



कवर्धा। सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने पर कबीरधाम जिले के गन्ना उत्पादक किसानों में उत्साह एवं खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के किसान हितैषी निर्णय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज कवर्धा में किसान संघों के पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में किसानों ने उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। किसानों ने उन्हें गन्ना भेंटकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान किसानों ने उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा को शक्कर की बोरियों से तौलकर उनका विशेष अभिनंदन किया।

कवर्धा में जिला पंचायत कार्यालय और विधायक कार्यालय के पास किसान संघो के पदाधिकारियों एवं किसानों ने उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल होने पर खुशी जताते हुए आभार व्यक्त किया। किसानों ने कहा कि गन्ने का मूल्य बढ़ने से जिले के हजारों गन्ना उत्पादक परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे खेती की बढ़ती लागत की भरपाई करने में सहायता मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि कबीरधाम जिला गन्ना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। ऐसे में गन्ने का बेहतर मूल्य मिलने से किसानों को अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल प्राप्त होगा तथा गन्ने की खेती को और प्रोत्साहन मिलेगा।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किसानों के स्नेह और आत्मीय अभिनंदन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि और खुशहाली राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी मेहनत से ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।

दुर्ग के ट्रांसपोर्ट नगर में 105.85 लाख रुपए की लागत से बनेगी सीसी रोड

दुर्ग। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेशभर में अधोसंरचना विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार का कार्य तेजी से जारी है। इसी कड़ी में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15, ट्रांसपोर्ट नगर में 105.85 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।



इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नागरिकों को बेहतर सड़क, सुगम आवागमन और सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

मंत्री श्री यादव ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में सीसी रोड के निर्माण से इस क्षेत्र की यातायात व्यवस्था काफी बेहतर होगी। इससे स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और वाहन चालकों को आवागमन में भारी सुविधा मिलेगी और परिवहन गतिविधियों को भी सुगमता प्राप्त होगी। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्ग शहर में नागरिकों के जीवन को और सुगम बनाने के लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास से जुड़े कई कार्य लगातार किए जा रहे हैं।

भाजपा सरकार ने पीएससी को मजाक बना दिया : दीपक बैज

रायपुर। भाजपा सरकार ने पीएससी को मजाक बना दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एक माह में पीएससी की दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं स्थगित की गयी है। पहले सिविल सेवा 2025 के साक्षात्कार को स्थगित किया गया, अब पुलिस एसआई और सूबेदार की परीक्षा को दोबारा स्थगित कर दिया गया। पीएससी भाजपा के शासनकाल में अपने कलेंडर का भी कड़ाई से पालन नहीं कर पा रही। इसके पहले एसआई भर्ती परीक्षा के परिणाम में अभ्यर्थियों के नामों में गड़बड़ी हुई थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पीएससी 2025 की सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा में 1:3 का पालन नहीं किया गया, इंटरव्यू के निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी इंटरव्यू नहीं पहुंच पाये। पीएससी की सब इंस्पेक्टर परीक्षा में अजीबो-गरीब नाम के अभ्यर्थी के उत्तीर्ण घोषित किये गये, क्या यही यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी की परीक्षा है।



खेल अनुशासन और एकाग्रता का प्रतीक हैं : टंक राम

तिल्दा में चमका राजनादगांव-राज्य स्तरीय वालीबॉल प्रतियोगिता के रोमांचक फाइनल में रायपुर सेक्टर को दी शिकस्त

रायपुर। दशहरा मैदान तिल्दा में आयोजित राज्य स्तरीय पुरुष वालीबॉल प्रतियोगिता का रोमांचक समापन समारोह आज संपन्न हुआ। कड़े मुकाबले और बेहतरीन खेल भावना के बीच खेले गए इस फाइनल मैच में राजनादगांव सेक्टर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रायपुर सेक्टर को हराकर प्रतियोगिता की विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर ली, जबकि रायपुर सेक्टर उपविजेता रहा।

समारोह के मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने विजेता और उपविजेता टीमों को शील्ड, पदक और नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री श्री



टंक राम वर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि खेल केवल हार-जीत का नाम नहीं है, बल्कि यह आपसी भाईचारा, अनुशासन और शारीरिक-मानसिक विकास का मजबूत माध्यम है। छत्तीसगढ़ की माटी में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए हरसंभव संसाधन और मंच उपलब्ध करा रही है। मंत्री श्री वर्मा ने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की छुपी हुई खेल प्रतिभाएं निखर कर सामने आती हैं। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, खेल संघ के पदाधिकारी, खेल प्रेमी और बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

राज्यपाल ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता इभानन साहू की सराहना

रायपुर। राज्यपाल डेका से आज लोकभवन में विशेष ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता श्री इभानन साहू ने मुलाकात की। ऑटिज्म से प्रभावित आकांक्षा लायंस इंस्टिट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट रायपुर के इस 22 वर्षीय छात्र ने हांगकांग में आयोजित



स्पेशल ओलंपिक ईस्ट एशिया रीजनल बॉलिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किया है। राज्यपाल ने इभानन साहू की उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी और उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की पहल की। श्री डेका ने कहा कि इभानन साहू की उपलब्धि अदम्य इच्छाशक्ति और कठोर परिश्रम का प्रेरणादायी उदाहरण है। उनकी सफलता न केवल छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। राज्यपाल ने आकांक्षा लायंस इंस्टिट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट रायपुर द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने संस्था के शैक्षणिक कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपने स्वेच्छानुदान मद से 10 कम्प्यूटर प्रदान करने की बात कही।

बसों में 75 फीसदी तक की अप्रत्याशित बढ़ोतरी से जनता पस्त : कांग्रेस

रायपुर। एक ही साल के भीतर दूसरी बार बस किराए में की गई बेतहाशा बढ़ोत्तरी को आम छत्तीसगढ़िया की जेब पर सीधा डकैती बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने आम



जनता, मजदूरों, किसानों और छात्रों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। एक साल के भीतर दूसरी बार बस किराए में भारी वृद्धि कर साधारण बसों का किराया 75 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। स्लीपर, एसी, सेमी-स्लीपर से लेकर लग्जरी बसों तक का सफर अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। महतारी वंदन के नाम पर 1000 की पब्लिसिटी करने वाली सरकार अब किराए के रूप में हर परिवार से हजारों रुपये वसूल रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस जनविरोधी फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग करती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार सुशासन और महंगाई कम करने के ढोल पीटती है, लेकिन हकीकत यह है कि एक साल के भीतर दूसरी बार बस किराया बढ़ाकर आम और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार या राज्य स्तर पर डीजल की दरों में कोई ऐसी अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित पीपीपीएसी की बैठक संपन्न



रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मूल्यांकन समिति की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा बिलासपुर के कोनी स्थित सिम्स मेडिकल कैंपस में निर्मित 240 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 100 बिस्तरों वाले स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत संचालित और रखरखाव करने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में पीपीपी मॉडल अस्पताल को 10 वर्षों के लिए बिलासपुर के कोनी में कुल 340 बिस्तरों वाले इन दोनों अस्पतालों को एक ही 10-वर्षीय लाइसेंस समझौते के तहत निजी डेवलपर, ऑपरेटर को संचालन और रखरखाव के लिए सौंपने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। अस्पताल में सरकारी योजनाओं (आयुष्मान भारत आदि) के लाभार्थियों और पूरी तरह नि:शुल्क मरीजों के लिए आरक्षित रहेंगे। केवल 20 प्रतिशत बिस्तरों का उपयोग पेड मरीजों के इलाज के लिए किया जा सकेगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी जैसी प्रमुख चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी।

बिजली विभाग डकैत बन गया है, उपभोक्ता को लूट रहा : कांग्रेस

रायपुर। सरकार बिजली बिल के साथ कोयले की कीमत का अतिरिक्त प्रभार जोड़कर उपभोक्ताओं से लूट रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अक्टूबर महिने में प्रति उपभोक्ता से 300 रू. से लेकर 1000 रू. तक



का अतिरिक्त प्रभार सरकार के द्वारा लगाया गया है। यह प्रभाव शुल्क बिजली बिल के अलावा उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भेजा गया है। जिन उपभोक्ताओं के ऑनलाइन केवल बिजली बिल पटाया तथा कोयला प्रभार शुल्क नहीं पटाया है, उनकी बिजली काट दी जा रही है। भाजपा सरकार ने बिजली विभाग को जबरिया वसूली का विभाग बना लिया है। इस साल अक्टूबर में जिनका बिजली बिल पटाने की नियत तारीख नहीं आई है। उनका भी पिछला प्रभार बकाया बता कर विद्युत कनेक्शन काट दिया जा रहा है। उपभोक्ता परेशान है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि बिजली क्यों काटी गयी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बिजली विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को लूटना है। बिजली आवश्यक जरूरत बन गयी है। उसका फायदा सरकार और बिजली विभाग उठा रहा, कभी अनुबंध भार से ज्यादा खपत बताकर दंड वसूला जा रहा तो कभी सेस लगाकर, कभी कोयले का अतिरिक्त प्रभार लगाकर वसूली की जा रही।

सर्वमंगला नगर जोन में आयोजित हुआ 'सरकार आपके द्वार' शिविर



कोरबा। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा के सभी जोनों में आयोजित 'सरकार आपके द्वार' शिविरों की अंतिम कड़ी में आज सर्वमंगला नगर जोन कार्यालय में शिविर आयोजित किया गया। उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि तथा महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत अध्यक्षता में शामिल हुईं। शिविर में आम नागरिकों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया और पात्र हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सरकार आपके द्वार' शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के साथ उन्हें विभिन्न योजनाओं की जानकारी और लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।

सेवा संकल्प अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा का शुभारंभ

मंत्री राजवाड़े की पहल पर 12 घंटे में लटोरी पहुंची एएलएस एंबुलेंस

सूरजपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की पहल पर सूरजपुर जिले के भटगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लटोरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) 108 एंबुलेंस की सुविधा मिली है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने आज सेवा संकल्प अभियान के तहत हरी झंडी दिखाकर एंबुलेंस को रवाना किया। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की घोषणा के महज 12 घंटे के भीतर एंबुलेंस लटोरी पहुंच गई।

इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सुशासन सरकार की प्राथमिकता है। हमारा निरंतर प्रयास है कि ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो



और जरूरतमंदों को समय पर उपचार मिल सके। लटोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एएलएस एंबुलेंस की सुविधा से गंभीर मरीजों और दुर्घटना पीड़ितों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने एंबुलेंस की मांग पर त्वरित पहल कर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से लटोरी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ होगा और जरूरत पड़ने पर मरीजों को बेहतर उपचार के लिए उच्च स्वास्थ्य संस्थानों तक सुरक्षित पहुंचाने में सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि 13 अक्टूबर को सूरजपुर जिले में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल से लटोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए ऐ एंबुलेंस उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। स्वास्थ्य मंत्री ने तत्काल एंबुलेंस उपलब्ध कराने की घोषणा की और घोषणा के 12 घंटे के भीतर एंबुलेंस लटोरी पहुंच गई।

ग्राम रियापाली में सामुदायिक भवन का होगा निर्माण, वित्त मंत्री चौधरी ने किया भूमिपूजन

रायगढ़। मुख्यमंत्रीविष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दे रही है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी ने आज रायगढ़ जिले के ग्राम रियापाली (घुटकूपाली) में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस भवन के निर्माण से ग्रामीणों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक आयोजनों के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा।

इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गांवों का सर्वांगीण विकास



सरकार की प्राथमिकता है। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार करते हुए ग्रामीणों की जरूरतों के अनुरूप विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन ग्रामीणों के लिए सामाजिक गतिविधियों, बैठकों और विभिन्न आयोजनों का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।

श्री चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी अधोसंरचना विकसित करना है, जिससे आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिले और गांवों में सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा मिले। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.